मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 16 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 16 – 22 अप्रैल 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

मानवाधिकार उल्लंघन ही आरएसएस–भाजपा की चारित्रिक विशेषता.....3

पाठ्य–पुस्तकों में इतिहास के विकृतीकरण की इतिहासकारों द्वारा भर्त्सना.....8–9

हैदराबाद में भाकपा और भाकपा (मा) की संयुक्त जन सभा

वामपंथी एकता की दिशा में एक मील का पत्थर

राम नरसिम्हा राव

हैदराबाद, 9 अप्रैल 2023: आज, रविवार को यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) एक संयुक्त जनसभा प्रदर्शनी मैदान में हुई। मीटिंग में दोनों पार्टियों के मंडल, जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। विशाल आम सभा में 10 हजार से भी अधिक लोग शामिल थे। मीटिंग के मंच पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी समेत दोनों पार्टियों के राज्य और केंद्र स्तर के अनेक नेता शामिल थे। भाकपा राष्ट्रीय सचिव डॉ. के. नारायणन, भाकपा (मा) के पोलित ब्यूरो सदस्य बी.वी राघवुलु, भाकपा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण–चाडा वेंकटरेड्डी एवं के. रामकृष्णा के अलावा दोनों पार्टियों के राज्य सचिवमंडल सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के कई सदस्य भी सभा में उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता भाकपा नेता कुनामेनी सम्बाशिव राव और भाकपा (मा) नेता तम्मीनेनी वीरभद्रम ने की। भाकपा तेलंगाना राज्य सचिवमंडल सदस्य ई. टी. नरसिम्हा ने सभा में आये श्रोताओं का स्वागत किया।

आम सभा को संबोधित करते हुए भाकपा महासचिव डी. राजा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी क्षेत्रों में संकट पैदा कर रही है; संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की भावना को नुकसान पहुंचा रही है। इसे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों की एकता के जरिये हराया जा सकता है। सभी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक क्षेत्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टियों को इस तथ्य को समझना चाहिए। भाजपा और आसएसएस पहले कहा करते थे– ''एक देश, एक संस्कृति, एक चुनाव और एक भाषा''। परंतु अब उन्होंने इस नारे को बदल दिया है। अब वे ''एक देश, एक पार्टी, एक नेता'' की बात कहते हैं और वह एक नेता है नरेन्द्र मोदी। उनका लक्ष्य भारत को एक हिन्दू राष्ट्र में बदलने का है। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था यह देश के लिए अत्यंत विनाशकारी बात होगी।

डी. राजा ने आगे कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसका चरित्र संघात्मक है। परंतु भाजपा और आरएस इसे एक हिन्दू राष्ट्र में बदलने के लिए दिन–रात एक किए हुए हैं। गवर्नरों को अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर कर रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा सर्वाधिक खतरनाक है और यह विचारधारा देश में आग की फैल जाएगी। निश्चय ही मोदी और आरएसएस के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा बेहद खतरनाक है।

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी जिस समय देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। कम्युनिस्टों ने उपनिवेशवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया, अनेक बलिदान किए जबकि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ही नहीं लिया। इतिहास ने कम्युनिस्टों के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी है कि भाजपा को पराजित किया जाए। कम्युनिस्टों की एकता ही दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी और फासिस्टी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर सकती है और भाजपा को हरा सकती है। यदि हम संसद और विधान सभाओं में कम्युनिस्टों की शक्ति को बढ़ा सके तो भारत के राजनीतिक नक्शे को बदला जा सकता है। वामपंथी एकता के लिए भाकपा और भाकपा (मा) को और अधिक एकताबद्ध होकर और और अधिक निकट आकर काम करना चाहिए,परस्पर विश्वास होना चाहिए और परस्पर और अधिक तालमेल बनाना चाहिए।

डी. राजा ने कहा, 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कोलकाता कांग्रेस ने भाकपा के तत्कालीन महासचिव सी. राजेश्वर राव ने दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के एकीकरण का प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को निर्विरोध पारित किया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि इन्द्रजीत गुप्ता, जो 1992 में भाकपा महासचिव चुने गए थे, और भाकपा (मा) के तत्कालीन महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत परस्पर मिलजुलकर, एकताबद्ध होकर काम काम किया करते थे। उन्होंने सभी राज्य समितियों को एक संयुक्त सर्कुलर भेजा था कि देश और अधिक मजदूर वर्ग के हित में तालमेल के साथ मिलकर काम करें और राज्य स्तर पर समन्वय समितियां बनाएं। परंतु इन समितियों ने कोई प्रगति नहीं की। फिर भी मैंने स्वयं ने और सीताराम येचुरी ने उनके साथ काम किया है और हम दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के महासचिव बने। हम अपनी पूरी ताकत के साथ और और अधिक तालमेल के साथ वामपंथी पार्टियों की एकता के लिए काम कर रहे हैं।

डी.राजा ने आगे कहा कि आज भाकपा और भाकपा (मा) के सभी स्तरों के नेताओं की मौजूदगी से यह संयुक्त जन सभा देशभर के लिए एक प्रेरणा की बात है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हाल में हुई 24वीं कांग्रेस ने भी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के पुनरेकीकरण का प्रस्ताव किया है।

डी. राजा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि अडानी मामले को संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए भेजा जाए, परंतु समिति में अपने बहुमत के बावजूद मोदी सरकार इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के तैयार नहीं। आखिर भाजपा इससे क्यों डर रही है?

जन सभा को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि जब तक नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से नहीं

हटाया जाता, हम अपने संविधान को नहीं बचा सकते। हमें अपने लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को जारी रखते हुए धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतों को एकताबद्ध करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि भाजपा को हराया जा सके। इसके लिए दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। देश में मोदी हवा बह रही है, यह एक प्रचार मात्र है, हकीकत नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया मोदी के हाथों में है और यह मीडिया दिन–रात प्रचार करता रहता है कि मोदी कोई नहीं हरा सकता। हाल में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए। कुल मिलाकर 180 सीटें थी जिनमें भाजपा 46 सीटों पर जीत सकी और 58 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई। नागालैंड में इसे केवल दो सीटें अधिक मिली और त्रिपुरा में भी वह दो सीटों के बहुमत से ही जीत सकी। त्रिपुरा में उसे अपनी पुरानी तमाम की तमाम 17 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा।

शेष पेज 12 पर...

जब सदियां अंधेरे में झोंक दी जाती हैं

संपादकीय

इस साल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री का अभिभाषण लाल किले से जब होगा, तो हम अपनी स्थापत्य कला, इसकी सुन्दरता, और इसके अतीत गौरव के बारे में नहीं सोच पायेंगे, क्योंकि अब लाल किले का अपना कोई इतिहास नहीं रहा। विश्व का सातवां आश्चर्य, ताजमहल आज एक आभासी सत्य होकर रह गया है। हमारे महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगौर ने इसे समय की अनंत सिलवटों में आंसू की एक बूंद कहा था। लेकिन यह भी सच है कि मध्यकाल के वर्षों को समय की धारा से अलग भी नहीं किया जा सकता। यहां, बाधा बनती है निरंतरता की समस्या, संस्कृति के कदमों को, विकास को, सर्जनात्मकता को और अंततः भारतीय सभ्यता और संस्कृति को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। उसकी विविधता में ही एकता है, जो स्वयं विविध है और उसे मिटाने की कोई भी कोशिश अनैतिक है।

हमारा पहला स्वातंत्र्य संग्राम, उपनिवेशवाद के विरूद्ध, 1857 में छेड़ा गया था और वह बहादुरशाह जफर, दिल्ली के अंतिम बादशाह, के नेतृत्व में लड़ा गया था। हमारा देश उनमें से है जहां विभिन्न क्षेत्रों से, संप्रदायों से, राजनैतिक विचारधारा से जन समागम सदियों से होता रहा है और आजादी की पहली लड़ाई में उन सबका सहयोग था। भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक ताक़त से आज़ाद कराने का दायित्व उन सबने अपनाया था। जब इस संघर्ष का वर्षों बाद अंत हुआ तो सहज ही देश में जनवाद की स्थापना हो गई, आधुनिक आदर्शों और मूल्यों के साथ संविधान की रचना हुई जिसमें हमारी जनता की विविधता का पूरा ख्याल रखा गया था। 1950 में इसे लागू किया गया, जिसमें प्रस्तावना में ही हमसे वादा किया गया कि हमारा देश सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी राष्ट्र होगा। इस सबमें कोई भी परिवर्तन संविधान का उल्लंघन माना जायगा। देश की जनता, जिसने देश का विभाजन झेला था, खून से भरे दिन देखे थे, अपनों को खोया था, उन्होंने देश की धर्मनिरपेक्षता, हमारी गंगा–जमुनी संस्कृति, और जनवाद को, पहले चुनाव में ही बहुमत से जिताया था। ये सारे मूल्य हमारे लिये जिन्दगी से भी अधिक पवित्र थे। इस सबके बावजूद चुनौतियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं।

दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दिनों से कई पन्ने, जो सालों में फैले हुए थे। उन्हें मिटा दिया गया। एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य–पुस्तकों में से अप्रैल के शुरूआती दिनों में ही कई हिस्से जो मुगल साम्राज्य की कई सदियों को समेटे हुए थे, उन्हें मिटा दिया गया। आजादी के बाद की भी कई घटनाओं का उल्लेख, जिनमें महत्मा गांधी की हत्या, गुजरात के दंगे आदि हटा दिये गये। जाति, वर्ग, धर्म और इन सबका सत्ता के साथ संबंध के संदर्भ को भी हटा दिया गया, क्योंकि छात्रों में ऐसी सचेतनता को प्रश्रय देना सत्ता को स्वीकार नहीं था। एन.सी.ई.आर.टी. ने इन सब क़दमों के औचित्य को कोविड और उसकी पैनडेमिक से जोड़ा है, जिससे छात्रों पर किसी भी तरह का तनाव डालना उन्हें स्वीकार नहीं था। इस सबका परिणाम यह है कि छात्रों को पंद्रहवीं सदी से सत्रहवीं सदी के मध्य तक के वर्षों के इतिहास से वंचित रखा गया। एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें देश की विशाल छात्र संख्या पढ़ती है। वह पूरे मुगल साम्राज्य के ज्ञान से वंचित रह जायगी।

ये सारे क़दम उठाए गये हैं छात्रों के ज्ञान की खोज़ को किसी भी तरह के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से! सचाई यह है कि हमारे पूरे देश में हिन्दू अस्सी प्रतिशत हैं और मुस्लिम चौदह प्रतिशत। इतिहास के विद्वानों के अनुसार, यह पूरी कोशिश राष्ट्र निर्माण के क्रम में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के किसी भी तरह के अवदान को प्रकाश में लाने से रोकने के लिये है। यह कोशिश पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी के समय भी हुई थी। 1999 से 2004 तक के सालों में, जब एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध इतिहासज्ञ आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर और अन्य अनेकों की लिखित पुस्तकों को रोक लिया गया था। यह मात्र हटाने की ही बात नहीं थी, बल्कि सत्य को विकृत करने की भी कोशिश थी। इतिहास की प्रमुख घटनाओं को प्रकाश से अंधेरे में उगलने की कोशिश थी। इतिहास के बारहवीं कक्षा के सिलेबस के अनुसार, महात्मा गांधी के विषय में कई तथ्यों को कुचल दिया गया। उदाहरण के लिये ''गांधी की हिन्दू और मुस्लिम एकता के प्रति प्रतिबद्धता से हिन्दू अतिवादियों में असंतोष और क्रोध फैलता रहा।..... आर.एस.एस. बैन हो गया। फिर ''.... .गांधी जी को विशेषकर वे लोग नापसंद करते थे जो चाहते थे कि हिन्दू बदला लें या फिर भारत भी हिन्दुओं का देश बन जाए, पाकिस्तान की तरह। गांधी जी सोचते थे देश की जनता गुमराह है। वे मानते थे कि भारत को मात्र हिन्दुओं का देश बनाना, इसे पूरी तरह नष्ट करना ही है।'' साथ ही ''.....उनकी लगातार हिन्दू–मुस्लिम एकता की कोशिशों से हिन्दू अतिवादी इतने उत्तेजित हो गए थे कि उन्होंने गांधी की हत्या की कई कोशिशें की ।'' लेकिन इस सबके बावजूद गांधीजी ने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया। उस हिस्से की जो पंक्तियां मिटाई नहीं गई, उनमें लिखा है, ''अंत में, जनवरी 30, 1948 को, एक ऐसा ही अतिवादी, नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी के पास गया जब वे प्रार्थना सभा की ओर आ रहे थे और बंदूक चलाकर पांच गोलियों से उन्हें घायल कर दिया, और हत्या कर दी।''

लेकिन बात सिर्फ उतनी ही नहीं थी। जिस हिस्से में देश की सांप्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा है, उनमें गांधी हत्या के बाद जनता के दुख और क्षोभ के बारे में जो कुछ भी लिखा गया, उनमें ये पंक्तियां बची हैं, ''.....गांधी जी की मृत्यु का देश की सांप्रदायिक परिस्थिति पर एक जादुई प्रभाव पड़ा। देश विभाजन से उपजी हिंसा बिल्कुल रूक गई। भारत सरकार उन सारी संस्थाओं पर टूट पड़ी जो सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बंदिश लगा दी गई। सांप्रदायिक राजनीति का प्रभाव भी धूमिल पड़ने लगा।''

छठी और बारहवीं कक्षा के पाठ्य–पुस्तकों से देश में जो भी विरोध, विद्रोह और सामाजिक आंदोलन हुए उन सबकों मिटा दिया गया। प्रमुख आंदोलनों की शुरूआत और विकास पर जो अध्याय, ''स्वाधीनता के समय से देश की राजनीति'' है, उसे मिटा दिया गया।

उसी किताब से मानवीय अधिकारों के हनन के संबंध में गुजरात सरकार की हिंसा को बढ़ने से रोकने में विफलता के ऊपर एक मिटा दिया गया हिस्सा है जिसमें कहा गया था, ''गुजरात की घटना से हमें चेतावनी मिलती है कि जब धार्मिक भावनाओं को राजनैतिक उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है तो हमें किस तरह के ख़तरे से जूझना पड़ सकता है। यह राजनैतिक जनवाद के लिये एक बड़ा ख़तरा है।''

वास्तव में, एन.सी.ई.आर.टी. का यह प्रयोग कई बार सामने आ चुका है, 2014 से अब तक यह तीन बार हो चुका है। पहली बार 2017 में, जब 1334 परिवर्तन किए गये थे और यह 182 किताबों में तथ्यों का नवीनीकरण और उनसे जुड़ने के संबंध में था। फिर यह 2019 में विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ घटाने के नाम पर किया गया।

लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, उसे सिर्फ अतुलनीय ही कहा जा सकता है।

कामरेड अब्दुल हलीम उर्फ लड्डन की श्रद्धांजलि सभा

शहीद नगर (गाजियाबाद): पार्टी कार्यालय शहीद नगर में कामरेड अब्दुल हलीम उर्फ लड्डन को श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने श्रद्धाजलि सभा में कामरेड के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिवार और उनके साथियों को सांत्वना दी और उनके परिवार का आह्वान किया कि जिस तरह पार्टी के प्रति कामरेड हाजी अब्दुल हलीम समर्पित थे। उसी तरह उनका भी सहयोग पार्टी को मिलता रहेगा तथा पार्टी भी उनके परिवार के लिए हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी रहेगी। जिला सचिव सईद अनवर ने कहा कि दिवंगत कामरेड अपनी अंतिम सांस तक पार्टी को अपनी सेवा देते रहे। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया जैसे कि पीड़ितों की सेवा करना, वंचितों को न्याय दिलाने, मंहगाई, बेरोजगारी, मुफलिसों के लिए सतत संघर्ष करना आदि उस पर चलकर ही हम सब उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर पार्टी जिला सचिव सईद अनवर ने सभा का संचालन करते हुए कहा कि सभी कमजोरों, वंचितों और शोषितों की लड़ाई को लेकर काफी गंभीरता से लड़ा जाएगा। श्रद्धांजलि सभा के वक्ताओं में प्रो. सी सदाशिव, महेश राठी, बृजेश सिंह चौहान (सीपीएम जिला मंत्री), पूर्णेन्दु शर्मा, अजय रस्तोगी, पार्षद पति यामीन अल्वी, पूर्व पार्षद पति यामीन अंसारी, डॉ. इदरीसी, जेड ए अंसारी, बब्बन और हाफिज अनीस अंसारी आदि शामिल थे। सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवार वालों ने भाग लिया। अध्यक्षता कर रहे अजीजुद्दीन मालिक ने भी कामरेड लड्डन को श्रद्धांजलि देते हुए सभा की समाप्ति की।

भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल का पार्टी मान्यता पर बयान

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्यों की बैठक 11 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय अजय भवन में हुई। पार्टी महासचिव डी. राजा ने सचिवमंडल सदस्यों को नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में बताया। भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल ने निर्वाचन आयोग की पार्टी मान्यता के बारे में अधिसूचना पर निम्न वक्तव्य जारी किया:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समृद्ध इतिहास और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में इसकी अग्रणी भूमिका पर और आजाद भारत के राष्ट्रीय एजेंडे को गढ़ने में इसकी भूमिका पर भारत निर्वाचन आयोग को उचित विचार करना चाहिए था।

भाकपा देश की प्राचीनतम राजनीतिक पार्टियों में से एक है और पूरे भारत में पार्टी की मौजूदगी और जन अनुसरण जारी है। देश को आगे ले जाने के लिए और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के प्रति संविधान की रक्षा करने में सर्वोच्च बलिदान देने में किसी से पीछे नहीं है।

पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता चुनाव आयोग भले ही वापस ले ले, भाकपा देश भर में जनगण के बीच अधिक जोश और निष्ठा के साथ काम करती रहेगी। इसके साथ ही साथ भाकपा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समेत समग्र चुनाव सुधारों, चुनावी बान्डस को खत्म करने और चुनाव में शामिल सभी भागीदारों के लिए बराबरी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार चुनाव के लिए राजकीय फंड देने के लिए अपने अभियान को तेज करेगी।

मानवाधिकार उल्लंघन ही आरएसएस–भाजपा की चारित्रिक विशेषता

महेश राठी

मोदी नीत भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दुनिया भर में चर्चा में बने हुए हैं। और आरएसएस निर्देशित मौजूदा मोदी सरकार इन मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का बचाव करने के लिए इसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का नाम देने की कोशिश भी करती है जो इस बात को इंगित करता है कि यह मामले अनायास नहीं बल्कि आरएसएस–भाजपा का राजनीतिक कृत्य हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों की एक लंबी कतार है। चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने और उसका स्पेशल दर्जा खत्म करने की बात हो अथवा उसकी प्रतिक्रिया में होने वाली गिरफ्तारियां हों, सरकार के विरोध अथवा मोदी पर सोशल मीड़िया में की गयी टिप्पणियों पर राजद्रोह लगाने के बचकाने मामले हों, सीएए और एनआरसी के विरोध में होने वाले विरोधों से निपटने के तरीके से लेकर उसमें शामिल लोगों पर लगने वाले यूएपीए जैसे मानवाधिकार हनन करने वाले कठोर कानूनों के दुरूपयोग के मामले हो अथवा मीड़िया की स्वतंत्र आवाजों की कुचलने की तरकीबें हों अथवा योगी सरकार और अन्य भाजपा सरकारों की बुलडोजर राजनीति भाजपा दीवार पर बड़े और साफ अक्षरों में लिखी इबारत की तरह है।

मोदी नीत भाजपा सरकार का प्रयास अपनी राजनीति में कोई नीतिगत सुधार लाने की अपेक्षा मानवाधिकार हनन के ऐसे मामलों की चर्चा पर रोक लगाने का ही अधिक है। ना केवल भारत में बल्कि मोदी सरकार का प्रयास विदेशों में भी होने वाली ऐसी चर्चाओं को रोकने भर का ही लगातार रहता है। विदेशों में होने वाली ऐसे चर्चाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की विदेश यात्राओं पर बेवजह रोक लगाने से लेकर उन्हें बिना कारण और बगैर ट्रायल के हिरासत तक में रखना शामिल रहा है। ऐस ही प्रयासों की कड़ी निन्दा करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निदेशक यामिनी मिश्रा का कहना है कि ऐसा जान पड़ता है कि दक्षिण एशियाई देश घोर पाखंड और दोहरे मापदंडों को मानते हुए मानव अधिकार कानून को चुनिंदा आधार पर लागू करते हैं। वे सिर्फ तभी मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करते हैं जब यह उनकी वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति के साथ संरेखित हो। लेकिन अगर इनके अपने हित दांव पर हों तो यह उन्हीं मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी साध लेते हैं। यह व्यवहार शर्मनाक है और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के पूरे ताने–बाने को कमजोर करता है। बेशक उन्होंने यह बात दक्षिण एशियाई देशों के संदर्भ में कही हो परंतु मानवाधिकारों को लेकर मोदी सरकार के व्यवहार के लिए उनका यह बयान एकदम सटीक है। इसके अलावा भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्रीनपीस और फोर्ड फाउंडेशन का हवाला देते हुए एनजीओ और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने और विदेशी फंड रोकने के लिए मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। कई अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने भी अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रोक पाने और नागरिक अधिकार संगठनों पर रोक लगाने के मोदी सरकार के प्रयासों और कृत्यों की समय समय पर कड़ी आलोचना की है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कड़ी निन्दा की जा चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2016 की रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रही है।

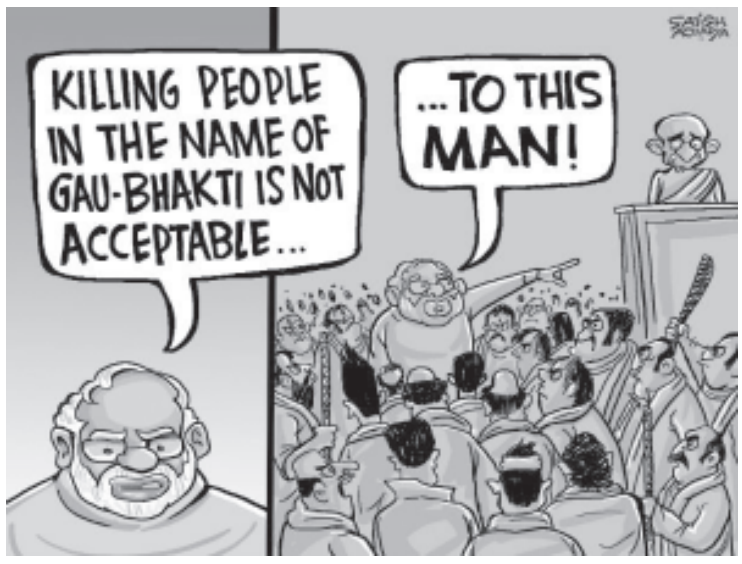

अपनी 659 पन्नों की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच रेखांकित कर चुका है कि सरकार का या फिर बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वाले एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड्स पर रोक लगाई जा रही है इससे अधिकतर मानवाधिकार संगठन सकते में हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की मीनाक्षी गांगुली का मानना है कि असहमति पर भारत सरकार का जो रवैया रहा है उससे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की परंपरा को धक्का लगा है। संगठन की रिपोर्ट में कथित तौर पर गौरक्षा के नाम पर लेकर हुई मुस्लिमों की हत्याओं का जिक्र करते हुए भाजपा के कुछ नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयानों से अल्पसंख्यकों पैदा हुए डर का हवाला दिया गया है। एमनेस्टी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी स्तर पर मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। एमनेस्टी रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जातीय हिंसा, भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव भी बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावटी–मेहता आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर आपराधिक और देशद्रोह की धाराएं लगाई हैं। इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी निशाने पर लेने के लिए भी मोदी सरकार पर उंगली उठाई गयी है। अभी हाल ही में बीबीसी को दिये गये अपने एक इंटरव्यू में दुनिया के नंबर एक अमीर माने जाने वाले एलन मस्क ने भी सोशल मीड़िया पर मोदी सरकार के द्वारा की जा रही सख्ती और भेदभाव पर सवाल उठाये हैं।

इसके अलावा हाल ही के दिनों में भाजपा के हमेशा से वैचारिक और राजनीतिक करीबी रहे अमेरिका की सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। जिसमें कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, पत्रकारों और सरकार से असहमति रखने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है और यह एक चिंता की बात है। अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के कारण अक्सर मोदी सरकार आलोचना से बचने वाले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा था कि भारत में कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी सरकार नजर बनाए हुए है। हालांकि मोदी सरकार द्वारा इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। इसके बावजूद भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई गयी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार या इसके एजेंटों द्वारा गैर–न्यायिक हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं, पुलिस या जेल अधिकारियों द्वारा लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जेल में परेशान किया जा रहा है। यह अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि नागरिक संगठनों ने इस बात पर चिंता जताई है कि मोदी सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को हिरासत में लेने के लिए अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) का इस्तेमाल करती है। भाजपा की बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बुलडोजरों का इस्तेमाल करके सरकार द्वारा ऐसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है जो उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं और ऐसे आलोचकों के घरों और आजीविका के साधनों को बर्बाद किया जा रहा है।

मानवाधिकार हनन के उल्लंघन पर यदि पिछले सालों की अमेरिकी सालाना विस्तृत रिपोर्ट को अक्षरस पढ़ा जाए तो वह भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों की एक डरावनी तस्वरी पेश करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में सरकारी एजेंसियों की ओर से अवैध, मनमाने ढंग से हत्याएँ हुई। जेलों में क्रूर और अमानवीय तरीके से कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है। राजनीतिक कैदियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा रहा है, मीडिया पर सरकार की ओर से अंकुश लगाया जा रहा है, पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारी हो रही है और उन पर केस दायर किए जा रहे हैं। लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने लिए लोगों पर आपराधिक केस लगाए जा रहे हैं या लगाने की धमकी दी जा रही हैं, इंटरनेट पर रोक लगाकर जनसंचार को बाधित किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि साल 2021 में भारत में 2116 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत में हुई। जो साल 2020 से 12 फीसदी ज्यादा अधिक थी। रिपोर्ट में कहा गया कि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में कोर्ट ट्रायल के इंतजार में 70 फीसदी कैदियों को तीन महीने या उससे अधिक समय तक जमानत नहीं मिल सकी। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई लोगों को सख्त कानून यूएपीए के तहत लंबे वक्त तक जेल में रखा। केंद्र की सरकार ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों पर यूएपीए लगाया और उन्हें हिरासत में लिया था। गैर–कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' होने या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में बिना कोई आरोप तय किए 180 दिनों तक हिरासत में रख सकती हैं। इस मामले में जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। साल 2018 से साल 2020 के बीच 4690 मामले यूएपीए के दर्ज किए गए और इनमें से केवल 149 मामले में ही अभियुक्त दोषी साबित हो पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। मोदी सरकार पर कई विदेशी मानवाधिकार संस्थाएं लगातार ये आरोप लगाती हैं कि वह अल्पसंख्यकों, राजनीतिक आलोचकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बना रही है। अमेरिका की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में समाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें मनमाने ढंग से आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन का है जिन्हें 28 महीने जेल में बंद रहना पड़ा और इस साल फरवरी में उन्हें जमानत मिली। सिद्दीक कप्पन पाँच अक्टूबर, 2020 को हाथरस गैंगरेप मामले की रिपोर्टिंग करने उत्तर प्रदेश जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ यूएपीए की धाराएँ लगाई गई। वहीं बीते साल जून में फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जुबैर मोदी सरकार, नेताओं और कई बार मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल की ओर से किए गए दावों का फैक्ट चेक करते रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर यूपी में छह और एफआईआर दर्ज हुई थीं लेकिन जुलाई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर एक करने का आदेश किया था। इसके बाद मोहम्मद जुबैर की रिहाई हो पाई। इसके अलावा भाजपा के बुलडोजर अभियान को भी रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है।

अमेरिकी रिपोर्ट के अलावा भी अन्य स्वतंत्र मानवाधिकार संगठन भी मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि हाल के कई सालों में भारत में मानवाधिकारों की स्थिति काफी बिगडी है। और मोदी सरकार के पिछले नौ

शेष पेज 4 पर...

प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे का विरोध

राज्य विभाजन के वादों को पूरा करो–जनता को ठगना बंद करो

केंद्र सरकार के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में विभाजन गारंटियों के कार्यान्वयन में लापरवाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद यात्रा के विरोध में भाकपा राज्य परिषद के आह्वान पर भाकपा हैदराबाद जिला परिषद ने शनिवार को सत्यनारायण रेड्डी भवन, हिमायत नगर, हैदराबाद में एक प्रदर्शन का आयोजन किया।

सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए सुबह से ही सत्यनारायण रेड्डी भवन की घेराबंदी कर दी थी। सी वेंकट रेड्डी, भाकपा तेलंगाना राज्य सचिवालय के सदस्य ई. नरसिंह, भाकपा हैदराबाद के जिला सचिव एस. छायादेवी, सहायक सचिव कामथम यादगिरि और बी. स्टालिन के साथ सैकड़ों भाकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर सत्यनारायण रेड्डी भवन पर प्रदर्शन किया। भाकपा कार्यकर्ताओं ने 'मोदी हटाओ देश बचाओ', 'मोदी वापस जाओ', 'निरंकुश मोदी मुर्दाबाद', 'राज्य विभाजन के वादों को पूरा करो' जैसे नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की तो उनके साथ कार्यकर्ताओं की तीखी बहस हुई, जिसके कारण तनाव की स्थिति बन गई। भाकपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिमायत नगर मेन रोड पर प्रदर्शन किया। भाकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भरसक कोशिशों के बाद गिरफ्तार किया और उन्हें विभिन्न थानों में ले गई।

सी वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य के प्रति केंद्र सरकार लापरवाह है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार बय्याराम स्टील उद्योग, रेल्वे कोच फैक्ट्री, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, ट्राइबल यूनिवर्सिटी और माइनिंग यूनिवर्सिटी जैसे वादे पूरा न कर तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने चेताया कि राज्य विभाजन के समय किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए जन आंदोलन को सघन किया जाएगा।

सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य विभाजन के अपने किसी भी वादे को पूरा किए बगैर तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने चेताया कि भाजपा तेलंगाना की जनता का तिरस्कार कर रही है और राज्य की जनता धोखा देने वाली पार्टियों को उचित सबक सिखाएगी।

ई टी नरसिम्हा ने कहा कि मोदी सरकार राज्यों की अवहेलना कर रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है और लोगों को झगड़ों में उलझा कर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा नीत सरकार जो कि धार्मिक राजनीति कर रही है वह जनता के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और अडानी एवं अंबानी को प्रोत्साहन दे रही है। राज्य विभाजन के वादों को पूरा किए बगैर विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखने के लिए हैदराबाद आने के लिए नरसिम्हा ने प्रधानमंत्री पर तेलंगाना की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि संविधान, जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर पानी फेर रहे हैं उन्हें तेलंगाना दौरे का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि रेल्वे विभाग ने रेल्वे को निजीकरण करने के रूप में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एम एम टी एस) ट्रेनों को पूरी तरह अनदेखा किया है, प्रचलित एम एम टी एस ट्रेनें अब ठप्प हो गई हैं और एम एम टी एस ट्रेनों की भारी कमी से यात्री परेशान हो रहे हैं। नरसिम्हा ने कहा कि एम एम टी एस की मौजूदा ट्रेनों को ट्रेफिक के अनुसार चलाने की जगह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एम एम टी एस के दूसरे चरण के रूप में 13 नई सेवाओं को लाउंच करना प्रचार मात्र है। एस छायादेवी ने कहा कि यदि भाकपा नेता राज्य विभाजन के वादों को पूरा करवाने के लिए निरंकुश प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करते हैं तो भाकपा नेताओं के घरों पर हमला करना और उन्हें पुलिस स्टेशनों में बंद करना गैर जनतान्त्रिक है। छायादेवी ने कहा कि राज्य भाकपा गैर कानूनी तरीके से पुलिस स्टेशनों में बंद करने की घोर भर्त्सना करती है।

वी एस बोस भाकपा तेलंगाना राज्य सचिवमंडल सदस्य, भाकपा वरिष्ठ नेता पी प्रेम पवनी, एटक राज्य सचिवमण्डल सदस्य बी वेंकटेशम, भाकपा हैदराबाद जिला कार्यकारिणी सदस्य जी चंद्र मोहन गौड़, पदला नलिनी, निर्लेकांति श्रीकांत, नगर नेता आर मल्लेश, शमशुद्दीन, अरुतल राजकुमार, आर बालकृष्ण, चौतन्य यादव, ओमर खान, लतीफ, आरिफ खान आदि गिरफ्तार किए गए थे।

मानवाधिकार उल्लंघन ही आरएसएस–भाजपा की चारित्रिक विशेषता

पेज 3 से जारी...

साल में देश में अल्पसंख्यकों व असहमति रखने वालों को यातनाएं देने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि भारत सरकार की नीतियां और गतिविधियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काम कर रही हैं। उसका कहना है कि भारत की हिंदुत्वादी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। वैसे भी यह बात जग जाहिर है कि मोदी और भाजपा के सत्ता में बने रहने का आधार यही ध्रुवीकरण की राजनीति है और इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मोदी सरकार और भाजपा कोई भी मौका गंवाती नहीं है। बल्कि उसकी लगातर कोशिश इस ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज करने की ही होती है। हालांकि मोदी सरकार इन आरोपों का खंडन करती रही है और उनका कहना है कि उसकी नीतियों का लक्ष्य सभी समुदायों का विकास है और उसके लिए वह अपने द्वारा गढ़े गये नारे सबका साथ, सबका विकास का हवाला भी देते हैं। परंतु अब नारा ही ठहरा। ऐसे ही एक नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी के सबसे विश्वस्त सिपहसालार गृहमंत्री अमित शाह ने कहा दिया था कि यह तो चुनावी जुमला था। संभव है कि सबका साथ, सबका विकास भी एक राजनीतिक जुमला ही हो।

सबका साथ, सबका विकास की असली कहानी 2022 में बुलडोज किये गये घरों और संपतियों से जाहिर हो जाता है। 2022 में भाजपा शासित राज्यों खासतौर पर यूपी में ऐसे लोगों के घर और दुकानें गिरा दीं, जो अक्सर सत्ता विरोधी आंदोलनों में शामिल हुए थे और जिनके घर गिराए गए उनमें अधिकतर मुसलमान थे। भाजपा और उसकी मानसिकता को जानने वालों का मानना है कि यह कार्रवाई देश के 20 करोड़ मुसलमानों को डराने के मकसद से की जा रही है। जबकि अधिकारी दावा करते है कि सारी कार्रवाई कानून के तहत की गयी है। 2014 में मोदी नीत भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की सालाना रैंकिंग 140 से लुढ़क कर पिछले साल 150 पर आ गई थी, जो अब तक की उसकी सबसे खराब रैंकिंग है। एक्सेस नाउ नामक संस्था के मुताबिक इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के मामले में भी भारत पांच साल से दुनिया का अव्वल देश बना हुआ है। भाजपा की इस मानसिकता को 2019 का नागरिकता कानून भी उजागर कर देता है। इस कानून को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने भी मूलभूत रूप से भेदभावपूर्ण बताया है। इस कानून के तहत भारत ने मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के ऐसे लोगों को अपने यहां नागरिकता देने का प्रावधान किया है, जिन्हें उसके पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण यातनाएं झेलनी पड़ी हों। साल 2019 में जब मोदी सरकार नया नागरिकता कानून लेकर आई तो इसे संयुक्त राष्ट्र ने मूल रूप से भेदभाव करने वाला बताया। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत का नया नागरिकता कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को तो नागरिकता देने की बात करता है लेकिन मुसलमानों को अपनी सूची में शामिल तक नहीं किया गया है। भाजपा की अल्पसंख्यसक खासतौर पर मुसलमान विरोधी मानसिकता को धर्म परिवर्तन विरोधी कानून और 2019 में भारतीय कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने जैसी कार्रवाइयों में भी पढ़ा जा सकता है।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद अचानक से बढ़ते राजद्रोह के मामले भी उसकी राजनीति का ही एक हिस्सा हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2015 में 30, 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। 2019 में देश में जो 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 96 लोगों में से 76 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और 29 को बरी कर दिया गया। इन सभी आरोपियों में से केवल दो को अदालत ने दोषी पाया गया। 2018 में जिन 56 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उनमे से 46 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और उनमें से भी केवल 2 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना। इसी तरह 2017 में जिन 228 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उनमें से 160 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और उनमे से भी मात्र 4 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना। 2016 में 48 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनमें से 26 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और केवल 1 आरोपी को ही अदालत ने दोषी माना। वहीं 2015 में इस कानून के तहत 73 गिरफ्तारियां हुई और 13 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई लेकिन इनमें से एक को भी अदालत में दोषी नहीं साबित किया जा सका। इसी तरह 2014 में 58 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन सिर्फ 16 के खिलाफ ही चार्जशीट दायर हुई और उनमें से भी केवल 1 को ही अदालत ने दोषी माना।

तथाकथित विरोधियों को बेवजह गिरफ्तार करना और बिना ट्रायल के जेल में रखना आरएसएस निर्देशित भाजपा की विचारधारा और राजनीति का हिस्सा है जिसे उसने कश्मीर में व्यापक रूप से अंजाम दिया। 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने खत्म किया था, उस वक्त हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस बात को अब लंबा समय बीत चुका है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से कइयों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो अब तक भी जेलों में बंद हैं। पिछले साल भारत सरकार ने देश की संसद को बताया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार 180 लोग फिलहाल जेलों में बंद हैं। सरकार ने ये भी कहा कि 1 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू–कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 613 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मोदी सरकार का मानवाधिरों को लेकर अपनाया जा रहा रवैया दरअसल, अनायास नहीं है, बल्कि यह उसकी फासीवादी सोच पर आधारित राजनीति का हिस्सा भर है। भाजपा के व्यवहार का यह रूप असल में, आरएसएस की फासीवादी सोच का राजनीतिक प्रकटीकरण है जो हमें आज मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जनवादी अधिकारों, जनवादी मूल्यों और जनतांत्रिक संस्थाओं पर सत्ता की कसती नकेल और सत्ता का लगातार बढ़ता केन्द्रीयकरण वास्तव में इस फासीवादी विचारधारा के व्यवहार को रेखांकित करने वाला है। जिसे जनवादी आंदोलनों के माध्यम से जवाब दिये जाने की जरूरत है और इसके लिए धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वाम ताकतों की एकजुटता ही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनी–81

शाकिर अली खान: 'शेरे – भोपाल'

अनिल राजिमवाले

शाकिर अली खान भोपाल रजवाड़े के अत्यंत ही सम्मानित जनप्रिय नेता थे। साथ ही भारत की आजादी से पहले तथा बाद में वे मध्य–भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जन्मदाताओं मं थे। यहां तक कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा था। वे बाद में 'शेरे–भोपाल' के नाम से सुविख्यात हो गए।

शाकिर अली का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। शुरू से ही उनमें परिस्थितियों से जूझने की विद्रोही भावना पैदा हो गई थी। अपना परिवार सम्भालने के लिए उन्हें एक 'कारखाना' या पुस्तक बाइंड करने के स्थान में कम उम्र में ही काम करना पड़ा था।

भोपाल में राजनैतिक जागरण

एक रजवाड़े के रूप में भोपाल की स्थापना 18वीं सदी के आरंभ में अफगान मुगल राजा दोस्त मोहम्मद खान द्वारा की गई थी। रजवाड़ा '19 तोपों की सलामी वाला रजवाड़ा' था। उसकी ब्रिटिश भारत के साथ संधि थी (1818–1947)। वहां की सरकारी भाषा फारसी थी जबकि हिन्दुस्तानी सामान्य जन की भाषा थी। भोपाल का क्षेत्रफल 6902 वर्ग मील था और 1901 में उसकी जनसंख्या 6,65,961 थी।

1891 और 1926 के बीच चार महिला नवाबों ने भोपाल पर शासन किया। उनके शासनकाल में राज्य में आधुनिक रेलवे, जन–संसाधनों, डाक सेवा तथा नगरपालिका का विकास हुआ। कुदसिया बेगम (1819) से आरम्भ होकर सभी महिला नवाबों ने पर्दा–प्रथा का पालन करने से इन्कार कर दिया।

भोपाल के राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी नेता

प्रोफेसर बरकतुल्ला खान भोपाल के जाने–माने राष्ट्रवादी नेता थे। वे 1887 में इंगलैंड चले गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाल हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपध्याय तथा अन्य क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आए। वे 1915 में काबुल में गठित अस्थाई भारतीय सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए। राजा महेन्द्र प्रताप इसके राष्ट्रपति थे।

बरकतुल्ला खान 7 मई 1919 को लेनिन से मिले और उनका प्राव्दा ने इंटरव्यू लिया। वे कम्युनिस्टों के काफी नजदीक थे।

इन सारी घटनाओं का शाकिर अली पर गहरा प्रभाव पड़ा।

पत्रकार के रूप में

शकिर अली 1926–79 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका रियासत और बाद में कलकत्ता के हिंद से जुड़े हुए थे।

वे 'एजुकेटेड पीपल्स एसोसिएशन' से भी जुड़े हुए थे। 1928 और 1931 के बीच पत्रकारों का शक्तिशाली आंदोलन फूट पड़ा। इस वक्त शाकिर राज्य प्रशासन में रैयतवारी मुहर्रिर का काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने भोपाल के सुल्तानिया इन्फैंट्री में 'नाइक' के पद पर काम किया। उपर्युक्त आंदोलन के दौरान उन्हें रेवेन्यू विभाग के काम में बर्खास्त कर दिया गया।

भोपाल में राष्ट्रवादी लहर

1933–37 के दौरान शाकिर अली और उनके साथियों ने सर्वेन्ट्स ऑफ भोपाल लीग (अंजुमने खुदमे वतन) का गठन किया। इसकी पत्रिका 'सुबह वतन' प्रकाशित की जाने लगी जिसमें शाकिर अली ने सक्रिय भूमिका अदा की और आगे चलकर वे इसके सम्पादक भी बने।

'सुबह वतन' बड़ा ही जनप्रिय हो गया। इसके दफ्तर के पास भारी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती। लोग इसकी प्रति खरीदने के लिए 10 रुपए तक दिया करते। भोपाल किले के पास आम सभाओं में हजारों की भीड़ जमा होती जहां अखबार बिका करता। यहां तक कि शाही परिवार के तथा नौकरशाही के लोग भी यह अखबार छिपकर पढ़ा करते।

1934 में विधान परिषद के चुनावों में सत्तार जमाल ने सरकारी उम्मीदवार को हराकर सीट जीत ली। 'सुबह वतन' ने उनका समर्थन करते हुए एक कार्टून प्रकाशित किया। इससे शासक भड़क गए। शाकिर अली, अहमद मक्की, सैय्यद हाफिज अली तथा भगवान दयाल को 22 अगस्त 1934 को अखबार के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध करते हुए हजारों लोग पुराना किला इकट्ठा हो गए। बाद में वे सभी रिहा कर दिए गए।

सितम्बर 1934 के सरकारी गजट में 'सुबह वतन' की तीखी आलोचना की गई। नए सिरे से गिरफ्तारियां होने लगीं।

बेरोजगारी के प्रश्न पर नौजवानों का बड़ा विद्रोह आरम्भ हो गया। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यहां तक कि सुल्तानिया इन्फैन्ट्री की 'बी' कम्पनी ने भी विद्रोह का साथ दिया और महल के सामने प्रदर्शन किया। इस टुकड़ी को तोड़ दिया गया और इसके सैनिकों को राज्य से निकाल बाहर किया गया।

शाकिर अली खान अपने साथियों के साथ अप्रैल 1935 में फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर 'गदर' संगठित करने का आरोप लगाया गया। उन्हें दो साल से भी अधिक की सजा दी गई।

जेल से छूटने के बाद शाकिर अली और उनके साथियों ने एक नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया 'सुबह वतन सानी'। इसे आगरा में प्रकाशित कर गुप्त रूप से भोपाल लाया जाता।

प्रजा मंडल सम्मेलन

1930 के दशक के दौरान भारत के रजवाड़ों में 'प्रजा मंडल' चल पड़ा।

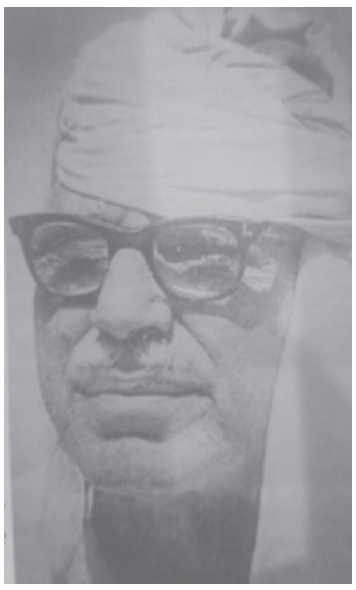

भोपाल राज्य प्रजा मंडल ने भी फैक्टरियों एवं दूकानों के मजदूरों एवं सामान्य जनता को गोलबंद किया। इसी दौरान मजदूर सभा का भी गठन हुआ।

अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस का आयोजन 1939 में लुधियाना में किया गया। इसका सभापतित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। भोपाल प्रजा मंडल इससे सम्बद्ध हो गई।

भोपाल प्रजा मंडल का गठन 14 फरवरी 1938 को एक गुप्त बैठक में हुआ। बैठक बज्मी साहेब के घर में हुई जिसमें शाकिर अली खान, सैयद अबू सईद बज्मी, तर्जी मशरीकी, अखलाक मो. खान, नूर बाज खान, सैयद जहूर आजमी, पं. चतुर नारायण मालवीय तथा अन्य ने हिस्सा लिया। संगठन का उद्देश्य था जिम्मेदार सरकार की सहायता और जनतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना।

शाकिर अली द्वारा उठाए गए सवाल

27 अगस्त 1938 को शाकिर अली ने हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि भोपाल के रजवाड़े में राजनैतिक सभाएं करना अत्यंत कठिन है, यहां तक कि निजी चारदीवारी के अंदर भी। मीटिंगें करने के लिए अनुमति के 90 प्रतिशत से भी अधिक अनुरोध अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

भोपाल कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत हर पोस्टमैन के साथ एक सिपाही अवश्य जाया करता। वह पोस्टमैन द्वारा पाने वाले को दिए गए हर सामान को जब्त कर लेता। यहां तक कि ब्रिटिश निवासी भी इसे अत्यंत भद्दा मानते और इसमें परिवर्तन की मांग किया करते।

जनता के दबाव में 1938 में राज्य प्रशासन ने बाहर से पांच नए अखबार आने की अनुमति प्रदान की।

शाकिर अली ने मध्य भारत राज्यों के जन सम्मेलन में जून 1939 में भाग लिया। यह सम्मेलन दोहद में हुआ।

भोपाल प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन

यह सम्मेलन 18–19 अक्टूबर 1938 को आयोजित किया गया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। शाकिर अली में जोरदार भावनात्मक तकरीर की जो सम्मेलन का स्वागत भाषण था। सम्मेलन में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। शाकिर अली ने बहस और आलोचनाओं का जवाब देते हुए समापन भाषण दिया।

रजवाड़ा के कुछ समर्थकों ने सम्मेलन में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। शाकिर अली उनके साथ सख्ती से पेश आए और सम्मेलन को बचा लिया।

सम्मेलन ने ओबैदुल्ला खान स्कॉल्टरशिप ट्रस्ट को नियमित रूप देने का फैसला किया।

भोपाल प्रजा मंडल के सारे राज्य में कई बड़ी आमसभा आयोजित कीं। इनमें शाकिर अली खान, चतुर नारायण मालवीय, जहूर हाशमी तथा अन्य वक्ताओं के भाषण हुए।

नवाब से शकिर अली की मुलाकात

राज्य में बढ़ते आंदोलनों से भोपाल के नवाब घबरा गए। उन्होंने मिर्जा आबिद हुसैन खान, एमएलसी, में जरिए शाकिर अली खान को मुलाकात करने का अनुरोध किया। वे दोनों चांदपुरा में मिले। उनकी मुलाकात का विवरण नवाब द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर में दिया गया। इसकी जानकारी आम जनता को दी गई।

यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। शाकिर अली ने इसकी जानकारी 12 अप्रैल 1939 को आयोजित एक आमसभा में दी। उन्होंने बातचीत के बारे में संतोष व्यक्त किया। नवाब ने 'बेरोजगारी–विरोधी समिति' के गठन की घोषणा की। इसमें नवाब के प्रतिनिधियों के अलावा जनता के पांच प्रतिनिधि शामिल किए गए थे जिनमें एक शाकिर अली खान भी थे। इस समस्या के हल की दिशा में नवाब ने कई कदम उठाने की घोषणा की।

26 नवम्बर 1938 से भोपाल प्रजा मंडल का अखबार, उर्दू साप्ताहिक भोपाल टाइम्स प्रकाशित किया जाने लगा।

प्रजा मंडल से संबंधित कई जन संगठनों का निर्माण किया गया: युवा, महिला, मजदूर तथा अन्य। यंगमेन्स पीपुल्स एसोसिएशन का गठन किया गया जिसकी 1942 के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शाकिर अली मजदूर सभा के सचिव बनाए गए। चार मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए और सेहोर जेल में रखे गए।

1946 आते–आते मजदूर सभा एक प्रभावशाली संगठन बन गया। इसमें बिजली, माचिस, पी.डब्लूडी, कुली, पत्थर–तोड़ मजदूरों इ. मजदूर और उनके संगठन शामिल हो गए। उसी वर्ष उनका व्यापक आंदोलन छिड़ गया। प्रजा मंडल ने 'मैदान' में उनके लिए कैम्प का आयोजन किया।

बाद में शाकिर अली मजदूर सभा के अध्यक्ष बनाए गए एवं एस.एम. कामिल महासचिव।

मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिकता का विरोध

शाकिर अली ने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस, लुधियाना, में 'भोपाल में इस्लामी राज्य' के खिलाफ आवाज उठाई। इस संदर्भ में उन्होंने 17 अप्रैल 1939 को एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ इस राज्य के सहयोग का इतिहास बताया और साथ ही भारतीय आजादी के आंदोलन का उसके द्वारा विरोध का भी। उन्होंने बताया कि किस तरह राज्य में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम सभाएं भंग करने के लिए शराब में धुत्त गुंडे भेजे जाते हैं।

भोपाल की मुस्लिम लीग ने शाकिर अली के इन वक्तव्यों की तीखी आलोचना की। उनके खिलाफ

शेष पेज 15 पर...

निहालगढ़ (पंजाब) में तेजा सिंह सुतन्तर की प्रतिमा का अनावरण

12 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी तेजा सिंह सुतन्तर की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निहालगढ़, जिला संगरूर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजा सिंह सुतन्तर इतने महान थे कि मैं सात जन्म भी ले लूं, उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सुतन्तर संसद सदस्य चुने गए उस समय भी उनके कंधे एक झोला लटका रहता था, वह संसद में होते तो भी उनके कंधे पर झोला होता। उनकी सादगी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह संसद में ही थे और उन्हें हृदयघात हो गया तो जब उनके झोले को खोलकर देखा गया तो उसमें आचार के साथ दो रोटियां पोने में रखी थी (गांव में लोग जब कहीं बाहर जाते हैं या काम पर जाते हैं तो एक कपड़े के टुकड़े में रोटियां रखकर ले जाते हैं। इस कपड़े को पंजाब में पोना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नतना कहते हैं)।

तेजा सिंह सुतन्तर का बचपन का नाम सुमन्द सिंह था। उनका जन्म गुरूदासपुर जिले के अलुआना गांव में हुआ था। जब पंजाब में गुरूद्वारों को ब्रिटिश समर्थन–प्राप्त महंतों के चंगुल से बचाने का संघर्ष चल रहा था, सुमन्द सिंह ने एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए तेजा गुरूद्वारे को महंतों से छुड़ाया था। इस जत्थे का नाम सुतन्तर जत्था रखा गया था। जब सुतन्तर जत्थे ने तेजा गुरूद्वारे को महंतों के कब्जे से छुड़ा लिया, उसके बाद वह तेजा सिंह सुतन्तर कहलाने लगे। हिन्दी के शब्द ''स्वतंत्र'' के लिए पंजाबी भाषा का

शब्द ''सुतन्तर'' है।

पंजाब में तेजा सिंह सुतन्तर का नाम लोक कथाओं में शामिल हो गया है। उन्होंने सामंती जमींदारों के खिलाफ लड़कर भूमिहीन किसानों को जमीन दिलायी; गुरूद्वारों को महंतों के कब्जे से छुड़ाने के लिए वर्षों तक चले संघर्ष में हिस्सा लिया और गुरूद्वारे छुड़ाए; देश के विभाजन के समय जबर्दस्त खून–खराबे के माहौल में भारी खतरा मोल लेते हुए उन्होंने अनेक लोगों की जानें बचाई। अल्पसंख्यक समुदाय के जिन सैंकड़ों लोगों की उन्होंने जान बचाई उनमें पंजाब के सुप्रसिद्ध नेता डॉ. सैफुद्दीन किचलू भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 1919 में जलियांवाला बाग में जिस जन सभा के दौरान जनरल डायर ने नरसंहार किया था, डॉ. किचलू उस सभा का संचालन कर रहे थे। सुतन्तर उनसे बड़े प्रभावित थे और डॉ. किचलू की प्रशंसा किया करते थे। जिस समय अकाल सेना ने डॉ. किचलू की हत्या का मंसूबा बनाया, तेजा सिंह सुतन्तर ने अमृतसर में उसकी सुरक्षा के लिए अपने 40 हथियारबंद लोगों को उनके घर पर तैनात कर दिया। उन रोमांचित क्षणों का विवरण देते हुए कम्युनिस्ट नेता इन्दर सिंह मुरारी ने अपने संस्मरणों में लिखा है: ''हम 40 लोग थे। सबके पास हथियार थे। हम दिन और रात किचलू के मकान के चारों तरफ रक्षा के लिए खड़े थे। हम एक महीने तक वहां डटे रहे। उसके बाद हम एक दिन उन्हें चुपके से निकाल कर दिल्ली ले गए। डॉ. किचलू अपने जीवन के अंतिम सांस तक तेजा सिंह सुतन्तर का आभार व्यक्त करते रहे। वह सुतन्तर का उल्लेख एक ''खुदा'' के तौर करते थे जिसने उनकी जान बचाई।

उनकी प्रतिमा के अनावरण के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरदेव सिंह अर्शी ने कहा: ''हम तीन किस्म की गुलामी में कुचले जा रहे थे। गांव में हमें सामंती जमींदारों ने गुलाम बना रखा था और उनके ऊपर थे शाही खानदान और अंग्रेज औपनिवेशिक मालिक। ये सुतन्तर ही थे जिन्होंने पहली बार पेप्सु मुजारा आंदोलन के दौरान तीनों किस्म की गुलामी के खिलाफ ऐसी बड़ी लड़ाई का नेतृत्व किया जो अब पंजाब में लोक गाथा बन गई है। उन्होंने सामंती जमींदारों से, जिनकी पुश्त पर पटियाला रियासत थी, 16 लाख एकड़ जमीन छीन ली और पंजाब के मालवा इलाके के 784 गांवों में भूमिहीन लोगों में बांट दिया''।

सुतन्तर संगरूर जिले के रहने वाले नहीं थे। लेकिन जमींदारों और राजशाही के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उनके कारण वह यहां के लोकनायक बन गए। संगरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 1971 में वह संसद सदस्य चुने गए।

वे बड़े ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने

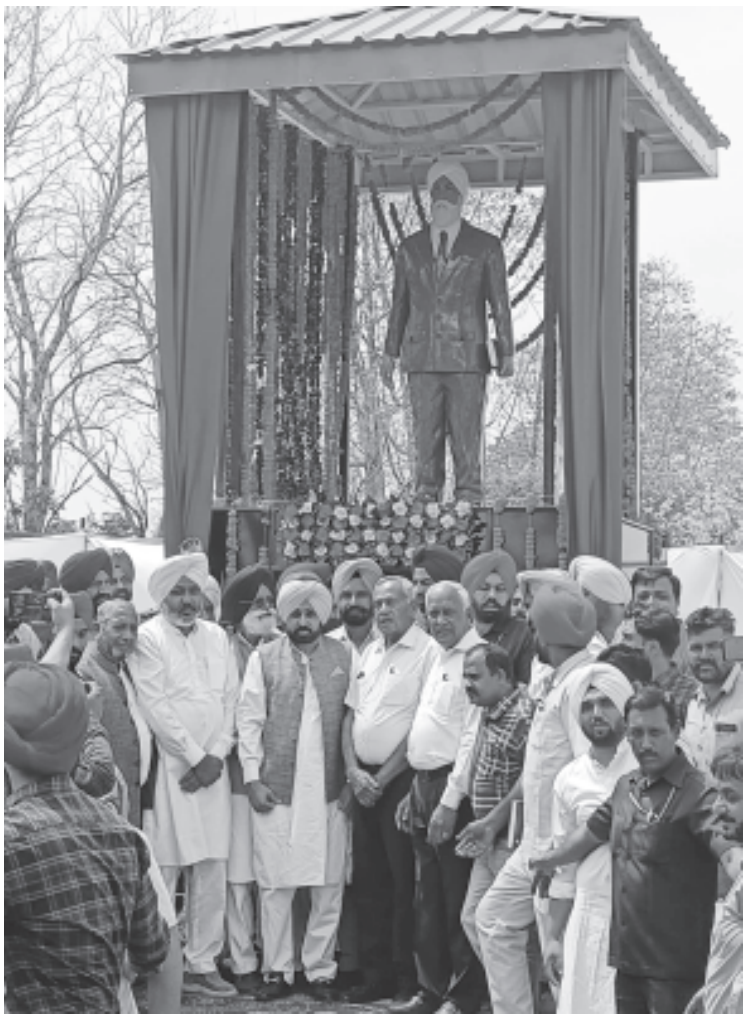

जीवन भर बड़ी–बड़ी कुर्बानियां दी। आजादी की लड़ाई में 8 साल जेलों में गुजारे। 12 अप्रैल 1973 को संसद में ही एक तकरीर के समय उन्हें जानलेवा हृदयघात हुआ। साथी सांसदों ने उन्हें संभाला। संयोग से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। साथी सांसदों ने जब उनके पार्थिव शरीर के साथ उनके सामान को भी संभाला तो उनके झोले में कुछ कागजात, कुछ फाइलें, कुछ दवाईयां और एक पोने में लिपटी दो रोटियां और अचार मिला। बाद में शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए इंदिरा गांधी ने कहा मैं अगर साक्षात नहीं देख लेती तो विश्वास ही नहीं कर पाती, इतना सादा इंसान इस संसद में चुनकर आया है। दुनिया के संसदीय इतिहास में मिसाल होगी, संसद की कैंटीन है जिसमें बहुत ही लजीज भोजन नाममात्र की कीमत पर मिलता है, तब भी एक एमपी अपने साथ दो रोटी लाता है अचार के साथ खाने को, कितनी सादगी, कितना समर्पण।

बाद में दूसरे नेताओं ने अपने शोक भाषण में कहा कि वे तो कई बार कामरेड को यही रोटियां खाते देख चुके हैं।

कामरेड विमल कांत चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि

दरभंगा, 13 अप्रैल 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी के पूर्व राज्य पार्षद सदस्य शत्रुघ्न झा की अध्यक्षता में पार्टी के पूर्व राज्य पार्षद सदस्य, लगभग 50 वर्षों तक जिला केंद्र में पूरावक्ती नेता के रूप में गरीब–मजदूर, छात्र–नौजवानों के हक–हकूक के लिऐ अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर करने वाले नेता कामरेड विमल कांत चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया।

संकल्प सभा में पार्टी के जिलामंत्री नारायण जी झा ने कहा कि कामरेड विमल कांत चौधरी जी ने पार्टी को पूरे मिथिलांचल में सीचने का कार्य किये। उनके नेतृत्व में कई बड़े जन आंदोलन हुए कई मोहल्ला और बस्तियों उन्होंने बसाने का कार्य किया। भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिला कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिलवाने का भी संघर्ष उन्होंने अंतिम समय तक करते रहे। उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिसे निकट भविष्य में भरपाई कर पाना काफी मुश्किल है। कामरेड विमल कांत चौधरी जी नेक दिल इंसान के साथ–साथ बेहतर सूझ–बूझ वाले और पढ़े लिखे नेता व वक्ता थे। उन्होंने डीएमसीएच

शरद कुमार सिंह

जैसे अस्पतालों में 24–24 घंटा खड़े होकर मिथिलांचल के निचले पयदानो के लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराने में मदद की थी। उनके नेतृत्व में कई पार्टी के विधायक और सांसदों ने चुनाव जीता था।

वहीं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के सहायक जिला मंत्री व मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि आज उनकी संकल्प सभा के अवसर पर हम लोग उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। उनके पूरे जीवन से आम लोगों को सीखने की जरूरत है। उनका मानना था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं मगर समाज के जीने वाले लोग विरले ही होते हैं। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए जिला कार्यकारिणी के सदस्य अहमद अली तमन्ने ने कहा कि वे पार्टी के बेहतर नेता तो थे ही साथ ही बेहतर अभिभावक के रूप में भी हम नौजवानों को समय समय पर दिशा–निर्देश देते रहते थे। हमलोग उनकी प्रेरणा से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। सभा को सीपीआई नेता विश्वनाथ मिश्र, सुधीर कुमार राय, राम उद्गार साह, रामबाबू सिंह, एआईवाईएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह, पंसस प्रतिनिधि रोहित चौधरी, चुल्हाई दास, गौतमकात चौधरी, बिहार चौधरी, गुड्डू यादव, शंकर यादव, निशांत ठाकुर, रौशन कुमार, प्रभाकर सिंह, प्रशनजीत प्रभाकर आदि ने संबोधित किया।

असंतोष काल के खिलाफ मजदूर वर्ग का संघर्ष

डा. युगल रायलु

क्रांतिकारी ऐतिहासिक दस्तावेज, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, की शुरुआती पंक्ति भविष्यसूचक साबित हुई है:

"अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है"।

ठीक गुलामी के दिनों से लेकर आधुनिक समय तक वास्तविक उत्पादक उन हड़पने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि किसी उत्पादक काम को किए बगैर मजदूरों और किसानों की मेहनत के फल का मजा लेते हैं।

महान अक्टूबर क्रांति के बाद से दुनिया भर में फैले हुए अधिकांश लोगों ने मजदूरों, किसानों, उत्पीड़ितों ने उस वर्ग के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया है जो आधुनिक दुनिया की रचना करने वाले बहुसंख्यक लोगों को दबा रहा है। पहले समाजवादी देश का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि सबसे कट्टर पूंजीवादी देशों को भी अपने स्वयं के कानूनी ढांचे में संशोधन करना पड़ा ताकि 'सामाजिक कल्याण' के कुछ विचारों की अनुमति दी जा सके, ताकि आने वाली क्रांति को कुछ समय के लिए दूर रखा जा सके।

सोवियत संघ के ढहने के बाद, कुछ प्रमुख पूंजीवादी लेखकों ने वाम विचारधारा के अंत की भविष्यवाणी की और कहा कि अब से बाजार इतिहास की दिशा और दशा तय करेगा। सोवियत संघ के ढहने के शुरुआती झटके के बाद वामपंथियों का उभार केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह हुआ। सभी देशों की ट्रेड यूनियनों ने अपनी ताकत को पुनर्जीवित किया और शक्तिशाली कॉर्पोरेट दिग्गजों और उनकी प्रायोजित सरकारों के हमले के खिलाफ खुद को स्थापित किया।

जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया श्रमिक–स्वामी संबंध को नया रूप दे रही थी तब कुछ समय तक ज्यादातर अखबार और पत्रिकाएं ट्रेड यूनियनों की सभी गतिविधियों की व्यर्थता के बारे में लिखते थे। इन अखबारों और पत्रिकाओं में यह तथ्य छिपा हुआ था कि पूंजीवाद खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा था ताकि वे दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी से हमला कर सकें। इतिहास में मजदूर आंदोलन के लिए सबसे कठिन समय में आगे बढ़ने, संघर्ष की मशाल की लौ को जीवित रखने का श्रेय उस युग के ट्रेड यूनियनों के नेताओं जाता है। वैश्वीकरण के शुरुआती उत्साह के बाद दुनिया भर में लोगों ने महसूस किया कि वैश्वीकरण के चंद्रमा का एक अंधकारमय पक्ष था– श्रमिकों और किसानों का एक नए और उच्च स्तर पर शोषण करना। पूंजीपतियों के एक 'एक ध्रुवीय' शासित दुनिया के सपने जल्द ही टूट गए।

अंतरराष्ट्रीय एकाधिकार पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित एक विश्व बाजार में अनियंत्रित लाभ कमाने के उनके परिकल्पित मार्ग पर हर जगह मजदूर वर्ग ने अपने संघर्षों से रोड़े बिछाए थे। लाभ कमाने के लिए कॉर्पोरेट दिग्गज जिस कुशलता से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब मजदूर वर्ग और किसानों के चौंपियन बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे थे! आज ट्रेड यूनियनें अपने संगठनात्मक कामों और गतिविधियों में प्रभावी रूप से डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी का बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर रही हैं।

बड़े कॉर्पोरेट के स्वामित्व और नियंत्रण वाले मीडिया ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों और किसानों के निरंतर संघर्ष के बारे में खबरें न देने से मजदूर वर्ग की एकता की शक्ति को नकार दिया है। सोशल मीडिया और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के कारण दुनिया भर में घट रही घटनाओं को खुद लोगों ने दुनियाभर के लोगों को बताया है। अब सच को छिपाना लगभग असंभव है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच कौन है जो अधिकांश जनता के न्याय के लिए लड़ रहा है।

यूरोप

फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रों द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की योजना के खिलाफ हजारों फ्रांसीसी वर्कर्स देश भर में ढाई महीने तक चले प्रदर्शनों में शामिल हुए। यह उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट था चूंकि वे यूरोपीय यूनियन के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक के राष्ट्रपति हैं। मेक्रों ने मार्च महीने में अपनी कार्यकारिणी शक्तियों के इस्तेमाल से, संसद को दरकिनार करते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का आदेश दिया था।

मेक्रों के आदेश से ट्रेड यूनियनें इससे सहमत नहीं हुई। उन्हें इसे अपने साथ धोखा समझा क्योंकि विधेयक पर संसद में चर्चा नहीं हुई और इस विधेयक पर उनके विचार नहीं सुने गए थे। अचरज की बात है कि इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। वे शायद इस मुद्दे की गंभीरता को समझते थे और अपनी भविष्य की समस्याओं को देख सकते थे। अनुमान लगाया गया था की प्रदर्शन के चरम बिन्दु पर लगभग 12.8 लाख वर्कर्स और अन्य मैक्रों के एकतरफा पेंशन सुधारों के विरोध में सड़क पर आए।

प्रतिष्ठित शहर पेरिस जो की अपनी सुंदर गलियों के लिए और एक आकर्षक माहौल के लिए जाना जाता है वह शहर एक विशालकाय कचरे का ढेर बन गया था जिसकी दुर्गंध शहर के ताकतवर लोगों की नाक में भर रही थी जिन्हें गुमान था कि वे कुछ नोटों को फेंक कर सब कुछ ठीक–ठाक करवा सकते हैं। इस देश व्यापी हड़ताल में सफाई कर्मचारियों ने अपने देशभाइयों का साथ दिया और मेक्रों और उसकी सरकार के लिए दुःस्वप्न बन गए।

फ्रांसीसी पेंशन को "पीढ़ियों के बीच एकजुटता" कहा जाता है जिसमें काम में लगी आबादी अनिवार्य पेरोल प्रभार अदा करते हैं उनके फंड के लिए जो रिटायर हो गए हैं। मुख्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में फ्रांस में सरकारी पेंशन की पात्रता उम्र सबसे कम है। सभी फ्रांसीसी वर्कर्स को सरकारी पेंशन मिलती है। इस पेंशन योजना ने इतने सालों से अच्छे से काम किया है। केवल भीमकाय कॉर्पोरेट इस "एकजुटता" से खुश नहीं हैं जो चाहते हैं कि वर्कर उनके लिए कम वेतन पर काम करें।

आम फ्रांसीसी ने फ्रांस के सभी ताकतवर कुलीनों को एक साफ संदेश भेजा है, और पराधीनता नहीं! लड़ाई जारी है! मजदूर वर्ग के एकता ताकतवर कुलीनों के शोषण के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है!

इंग्लैंड में, हजारों इलेक्ट्रिशन, टेक्निशियन, क्रेन ऑपरेटर, पाइप फिटर और नॉर्थ सी ऑइल के दूसरे वर्कर्स समेत हजारों वर्कर्स ने वेतन बढ़ाने और काम की बेहतर परिस्थितियों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। यह प्रस्तावित हड़ताल नॉर्थ सी ऑइल के सारे उत्पादन को रोक सकती है। इंग्लैंड में सब कुछ ठीक नहीं है।

जर्मनी में वर्डी यूनियन ने बेहतर वेतन के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। ब्रेमेन, लोअर सक्सोनी और उत्तरी राइन में सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो सार्वजनिक परिवहन ठप्प हो सकता है।

यूरोप के ज्यादातर देश 2023 के पहले चार महीनों में मजदूर हड़तालों में घिरे हुए थे। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और दूसरे यूरोपिय देशों मे दक्षिणपंथी सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में मजदूर ट्रेड यूनियनों की बढ़ती ताकत देखने को मिल रही है। वर्कर्स ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है।

एशिया

एशिया के ज्यादातर देशों में केन्द्रीय शक्ति का पुनरुतथतान दिख रहा है। चाहे वह भारत हो या श्री लंका या पाकिस्तान, वर्कर्स और किसानों ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपने संघर्ष को धारदार कर दिया है।

अभी हाल तक सबसे खराब राजनीतिक संकट से निकले श्री लंका में 15 मार्च 2023 को श्री लंका के स्वास्थ्य कर्मियों, रेल्वे, बंदरगाह और दूसरे शासकीय कर्मचारियों ने आयकर में बढ़ोतरी, बिजली के दाम बढ़ाने के विरोध में अब तक कि मजबूत हड़ताल देखने को मिली। पूरा श्री लंका मानो कि उस शासक वर्ग की अक्षमता के खिलाफ उबल पड़ा है जो कि मजदूर वर्ग की पीड़ा से बेखबर था।

कोरिया

ट्रेड यूनियनों के कोरियाइ कनफेडरेशन ने कॉउपांग इट्स नाम के स्थानीय प्लेटफॉर्म आधारित फूड डिलिवरि सर्विस के खिलाफ उस समय हड़ताल कर दी जब इसने प्रति डिलिवरि सर्विस के मूल मुवावजे को 3100 वान से घटाकर 2500 वान करने का निर्णय लिया। कोरिया में एक डॉलर की कीमत 1319 वान है। मूल सर्विस फीस बढ़ाने, अतिरिक्त1 किलोमीटर पर उचित मानदंड लागू करने और राइडर्स के बीमा भुगतान के समर्थन की मांग ट्रेड यूनियनों के कोरियाइ कनफेडरेशन ने की थी। इसी तरह की हड़ताल उसके पड़ोसी देश थाईलैन्ड में भी संगठित की गई थी, थाईलैन्ड में यूनियनों ने प्रति डिलिवरि फीस रेट 30 भाट करने की मांग की थी। यह स्वाभाविक है कि ट्रेड यूनियन इन कंपनियों से जिनमें ये वर्कर काम करते हैं उनसे वर्कर्स के श्रम के उचित मुआवजे की मांग करती है।

भारत

कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी सभी तरकीबों का इस्तेमाल करता है मजदूर वर्ग को बाँटने के लिए ताकि इसके लड़ने की ताकत घट जाए। मजदूर वर्ग ने अपने अनुभवों से इस सच्चाई को समझ लिया है और मजदूर वर्ग पहले से अधिक सतर्क हो गया है। हाल ही में जब भारत में ट्रेड यूनियनों ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, उनकी मांगों में अपने वर्तमान किसान भाइयों के लिए उचित समर्थन मूल्य की मांग भी थी।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर भारत के 2000 लाख मजदूर दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल पर थे। उनकी मांगे थी:

मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को रद्द करो

बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण बंद करो

'किसान विरोधी' कानूनों को रद्द करो

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के आवंटन की राशि बढ़ाओ

आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील समेत सभी अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को वैधानिक न्यूनतम वेतन दो

हड़ताली कर्मचारी अपने लिए कोई वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। हड़ताली कर्मचारी किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए सड़कों पर थे। यह नरेंद्र मोदी नीत दक्षिणपंथी भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) को छोड़कर अन्य सभी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था। वित्त मंत्री को तुरंत एक बयान देना पड़ा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही है।

दक्षिणपंथी सरकारें मजदूर वर्ग के विकसित अंतःकरण से डरती हैं। उनके कॉर्पोरेट मालिक मजदूर वर्ग की एकता से डरते हैं। इस एकता को तोड़ने के लिए हिंदू–मुस्लिम दंगों का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोगों द्वारा आसानी से किया जाता है। उनका दुर्भाग्य कि, भारत के मजदूर वर्ग ने सरकार के गंदे कुचक्रों को देखा है और मजदूर वर्ग कोई समझौता करने की मुद्रा में नहीं है।

दक्षिणपंथी सरकार को सबसे बड़ा झटका किसानों से मिला। किसान यूनियनों के संयुक्त फोरम के नेतृत्व में किसान तेरह महीनों तक गर्मी, बारिश और सर्दी की परवाह किए बिना दिल्ली के बॉर्डर पर टिके रहे, भारत के मजदूर वर्ग ने किसानों का समर्थन किया था। इस आंदोलन के दौरान सात सौ पचास साथियों की जान गई। आंदोलन के दबाब में आखिरकार तथाकथित शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकतरफा रूप से कठोर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

किसानों की शानदार जीत ने सभी संघर्षरत जनता को यह सिखाया है कि उत्पीड़कों के खिलाफ किसी भी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली जरूरत संघर्षरत मजदूर वर्ग की एकता है। सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे हमेशा अल्प संख्या में होते हैं। बहुमत को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए।

एक बार फिर से मार्क्स और एंगल्स के शब्दों में:

"दुनिया के मजदूरों एक हों! तुम्हारे पास गरीबी और भूख की जंजीरों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है, और जीतने के लिए सारी दुनिया है!"

पाठ्य–पुस्तकों में इतिहास के विकृतीकरण की इतिहासकारों द्वारा भर्त्सना

आर.एस.यादव

एनसीईआरटी की पाठ्य–पुस्तकों से कई अध्यायों के हटाए जाने पर 250 से अधिक प्रसिद्ध इतिहासकारों ने चिंता जताई है और कहा है कि पाठ्य–पुस्तकों से इस तरह अध्यायों को हटाया जाना एक विभाजनकारी और पक्षपातपूर्ण कदम है। इतिहासकारों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि पाठ्य पुस्तकों में जिस तरह बदलाव किए गए हैं वह भारत के संविधान और संस्कृति के खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा है कि पाठ्य–पुस्तकों से इस प्रकार अध्यायों को हटाना सरकार के पक्षपातपूर्ण एजेंडे को उजागर करता है।

एनसीईआरटी ने अन्य अनेक बदलावों समेत, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पुस्तकों में जो बदलाव किए हैं, उनमें शामिल हैं:

– मुगल इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटा दिया है;

– महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध की जानकारी हटा दी गई है;

– 2002 के गुजरात दंगों के सभी संदर्भ एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों से हटा दिए गए हैं;

– फिराक गोरखपुरी की एक गजल के कुछ अंश, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविता ''गीत गाने दो मुझे'', ''चार्ली चैपलिन और हम सब'', गजानंद माधव मुक्तिबोध लिखित कविता ''नई जन्म की कुंडली'' और नरेन्द्र शर्मा की कविता ''नींद उचट जाती है'' जैसे अध्याय पुस्तकों से हटा दिए गए हैं।

– बारहवीं कक्षा की इतिहास की किताबों में छात्रों को अकबरनामा एवं बादशाहनामा, मुगल शासकों और उनके साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, रंग–चित्रण, आदर्श राज्य, राजधानी और दरबार, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात्य वर्ग, साम्राज्य और सीमाओं के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा;

– विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य और शीतयुद्ध का दौर जैसे अध्यायों को भी बारहवीं कक्षा की नागरिक शास्त्र की पुस्तक से पूरी तरह हटा दिया गया है;

– बारहवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध ''राज धर्म'' टिप्पणी को हटा दिया गया है;

– हिन्दू कट्टरपंथियों की गांधी जी के प्रति नफरत, गांधीजी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध जैसी बातें अब पाठ्य–पुस्तकों में नहीं होंगी।

– कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में ''इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क'' शीर्षक अध्याय से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम निकाल दिया गया है। पुस्तक में एक पैराग्राफ इस प्रकार था: ''संविधान सभा में विभिन्न विषयों के संबंध में आठ समितियां थी। सामान्यत:,जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अम्बेडकर इन समितियों की अध्यक्षता किया करते थे। ये सब लोग अनेक बातों पर एक–दूसरे से सहमत नहीं थे। अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी के कटु आलोचक रहे थे और उन पर आरोप लगाते थे कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने पर्याप्त काम नहीं किया। नेहरू और पटेल अनेक मुद्दों पर परस्पर सहमत नहीं थे। परंतु उन सबने मिल–जुलकर काम किया''।

उपरोक्त पैराग्राफ के जिस वाक्य में मौलाना आजाद का नाम है, नई पुस्तक में उस वाक्य से मौलाना आजाद का नाम निकाल दिया गया है और यह वाक्य अब इस प्रकार है: ''सामान्यत:,जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल या अम्बेडकर इन समितियों की अध्यक्षता किया करते थे''।

इस तरह का बदलाव करने वाले अज्ञानी एवं शातिर लोगों को शायद यह अच्छा नहीं लगता कि जब 1946 में भारत की नई संविधान सभा के चुनाव हुए थे, मौलाना आजाद ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए प्रमुख भूमिका अदा की। भारत की आजादी के सवाल पर कांग्रेस के जिस प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश केबिनेट मिशन के साथ वार्ता में हिस्सा लिया था, उसके नेता मौलाना आजाद थे। लगता है भाजपा /आरएसएस को मौलाना आजाद से खास चिढ़ है तभी तो वित्त मंत्रालय ने उनके नाम से दी जाने वाली छात्रवृत्ति ''मौलाना आजाद फैलोशिप'' को बंद कर दिया है। मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं की पहल थी कि प्राइमरी से भारत में मुख्य एवं अनिवार्य शिक्षा का दौर शुरू हुआ था।

– 11वीं की समाज विज्ञान की पुस्तक के दसवें अध्याय में जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय के संबंध में एक वाक्य था: ''भारतीय संघ में जम्मू एवं कश्मीर का विलय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत इस राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित था''।

इस वाक्य को पुस्तक से निकाल दिया गया है।

भारतीय इतिहास कांग्रेस द्वारा भर्त्सना

इन बदलावों की भर्त्सना करते हुए भारतीय इतिहास कांग्रेस ने कहा है कि एनसीईआरटी ने इतिहास के पाठ्यक्रम और पाठ्य–पुस्तकों में जो बदलाव किए हैं वह उससे अत्यंत चिंतित है। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने इतिहासकारों से अनुरोध किया है कि वे ''इतिहास के विकृतीकरण'' के खिलाफ आवाज उठाएं।

भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर केशवन वेलुतक और सचिव प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में इन बदलावों द्वारा निकलने वाले नतीजों के संबंध में आशंकाएं व्यक्त करते हुए कहा गया है कि इतिहास के पाठ्यक्रम और पाठ्य–पुस्तकों में जो बदलाव किए हैं उसके फलस्वरूप ''हमारे अतीत के संबंध में सुस्पष्ट पूर्वाग्रहग्रस्त एवं तर्कशून्य समझ पैदा होगी''।

बयान में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इतिहास के बैचलर कोर्स के लिए जो सिलेबस बनाया है उसमें भारत के आर्य मातृभूमि होने के ''सम्मान'' का और महाकाव्यों को संभावित ऐतिहासिक वृतान्त होने का दावा किया गया है और उसमें प्राचीन भारत के हिस्से में जाति व्यवस्था के तमाम उल्लेख को निकाल दिया गया है। उसमें साफतौर पर कहा गया है कि जाति व्यवस्था की संस्था भारत में इस्लाम के आने के बाद पैदा हुई।

मुगल बादशाह अकबर और विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता की उसकी नीति को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि ''इस प्रकार, बैचलर कोर्स के विद्यार्थी अब मुगलकाल के सांस्कृतिक या बौद्धिक घटनाक्रमों के बारे में नहीं जान पाएंगे''।

बयान में कहा गया है कि समूचे के समूचे हिस्सों और कुछ वाक्यांशों और वाक्यों को पाठ्य–पुस्तकों से हटाकर निर्धारित पाठ्य–पुस्तकों में इतिहास को तोड़ने–मरोड़ने और मिथ्या प्रस्तुति को शुरू कर दिया गया है। जिस मुगल खानदान ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की उसे इतिहास से पूरी तरह निकाल दिया गया है। इतिहास को इस हद तक तोड़ा–मरोड़ा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है।

भारतीय इतिहास कांग्रेस के सचिव और प्रसिद्ध इतिहासकार सैयद अली नदीम रिजवी ने इन बदलावों की भर्त्सना करते हुए कहा है: ''इतिहास बदलता रहता है, ऐसे में कुछ अरसे के बाद ये जरूरत महसूस होती है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें बदलाव किया जाए। बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव हमेशा से ही तथ्यों के आधार पर होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कई सालों से इतिहास को अपनी मर्जी के मुताबिक लिखने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से धीरे–धीरे इतिहास को मिटाकर उसकी जगह मिथकों को दी जा रही है। 2014 के बाद से बार–बार इतिहास को अब एक तरह से काल्पनिक इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है''।

प्रोफेसर रिजवी ने एनसीईआरटी के इस तर्क को खारिज किया कि मुगलों को इतिहास की पुस्तकों से हटाया नहीं गया है बल्कि उनसे जुड़ी सामग्री को कम किया गया है। प्रोफेसर रिजवी ने कहा कि ''पुस्तकों में मुगलों से जुड़ा जो हिस्सा मौजूद है, उसे किसी खास उद्देश्य के तहत रखा गया है। उन्होंने उन चुनिंदा हिस्सों को रखा है, जहां ये दिखाया जा सके कि मुगलों ने हिन्दुओं से जंग की; लेकिन जहां ये दिखाया जा सकता है कि मुगलों ने इस समाज और देश को बनाने के लिए काम किया, उसे हटा दिया गया है.....महाराणा प्रताप को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन महाराणा प्रताप को अकेले रखकर हीरो नहीं बनाया जा सकता, वहां अकबर की मौजूदगी जरूरी है। लेकिन अकबर ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया और एक सहनशील समाज बनाया, उसे हटा दिया गया है''।

ये उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य–पुस्तकों के जिन अध्यायों को और अंशों को हटाया गया है वह किसी एकेडेमिक या शिक्षा शास्त्रीय सोच पर आधारित पर नहीं है बल्कि यह बदलाव आरएसएस–भाजपा की सांप्रदायिक सोच और इतिहास की विकृत समझ और इतिहास के विकृतीकरण की सुविचारित योजना के अनुसार किए गए।

देश के जाने–माने 250 से अधिक इतिहासकारों ने इन बदलावों का विरोध करते हुए निम्न बयान दिया है:

बारहवीं कक्षा और अन्य कक्षाओं की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से कुछ समूचे अध्यायों को हटाने का एनसीईआरटी का हाल का फैसला अत्यंत चिंता की बात है। पाठ्यक्रमों के बोझ को हल्का करने के लिए कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन की अवधि का इस्तेमाल करते हुए एनसीईआरटी ने एक विवादास्पद प्रक्रिया शुरू की जिसमें इतिहास के अनेक विषयों को हटाना शामिल है। छठी से बारहवीं कक्षा तक के इतिहास और राजनीति विज्ञान की पाठ्य–पुस्तकों में से हटाए गए अध्यायों में शामिल हैं: मुगल दरबारों का इतिहास, गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे, आपातकाल, दलित लेखकों का उल्लेख, नक्सलवादी आंदोलन, समानता के लिए संघर्ष।

कोरोना महामारी के बाद जब शिक्षा वापस पटरी पर आ रही है और शिक्षा का ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी पुस्तकों के नए संस्करणों में कुछ बातों को हटाया जाना अब सामान्य बात बन गई है।

इस प्रकाश में यह भारी चिंता की बात है कि कक्षा बारहवीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के खंड दो से मुगलों को हटा दिया गया है जबकि खंड तीन से आधुनिक भारत के संबंध में दो अध्याय हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी के अलावा इतिहासकारों और स्कूल शिक्षकों की टीमों ने इन पुस्तकों को तैयार किया था। उन टीमों के किसी भी सदस्य से सलाह–मशविरा करने की कोई कोशिश तक नहीं की गई। इन पुस्तकों को सलाह–मशविरे और व्यापक विचार–विमर्श की प्रक्रिया के जरिये तैयार किया गया था। यह चीज न केवल अंतर्वस्तु के लिहाज से बल्कि अध्यापन के लिहाज से भी मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण थी, जिससे मिडल से लेकर सीनियर स्कूल स्तर तक एक ज्ञान एवं समझ में एक जैविक एकता एवं क्रमिक विकास सुनिश्चित होता था। पाठ्य पुस्तकों को यथासंभव समावेशी और इस तरह का बनाने की कोशिश की गई थी कि वह उपमहाद्वीप के अंदर और व्यापक दुनिया, दोनों के मानवीय अतीत की समृद्ध एवं प्रचुर विविधता की भावना की रक्षा करे। अत: अध्यायों/अंशों को हटाया जाना न केवल इसलिए अत्यंत समस्यात्मक है कि छात्र इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को सीखने से वंचित रह जाएंगे बल्कि इस लिहाज से भी कि वह वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक मूल्यों से भी वंचित रह जाएंगे। स्कूल पाठ्य–पुस्तकों के समय–समय पर संशोधन की आवश्यकता को हम समझते हैं, परंतु यह काम वर्तमान ऐतिहासिक ज्ञान एवं पांडित्य के सम्बंध में मतैक्य के साथ समन्वय कर ही किया जा सकता है। परंतु पाठ्य–पुस्तकों के संशोधन में कुछ अध्यायों/हिस्सों को चुनिंदा तरीके से हटाए जाने से पता चलता है कि फूटपरस्त राजनीति शैक्षणिक सरोकारों पर हावी हो गई है।

एनसीईआरटी के डायरेक्टर के अनुसार, स्कूल पाठ्य–पुस्तकों के वैज्ञानिक पुनर्गठन के एक हिस्से के तौर पर कुछ अध्याय/ अंश हटाए गए हैं। यह काम छात्रों पर बोझ हटाने के

लिए किया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार, महामारी के दौरान छात्रों को पढ़ाई के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और महामारी के बाद की अवधि में छात्र महसूस कर रहे थे कि उन पर पाठ्यक्रम का बहुत अधिक बोझ है। एनसीईआरटी के अनुसार, विभिन्न कक्षाओं और विषयों में कुछ अध्याय ओवरलैप (अतिव्यापित थे यानी एक दूसरे के कुछ अंश को ढक) रहे थे। बोझ के तले दबे छात्रों के फायदे के लिए कुछ विषयों को कम करना तर्कसंगत था। एनसीईआरटी के अधिकारियों ने इस बात से इंकार किया है कि वैज्ञानिक पुनर्गठन के इस कदम के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक उद्देश्य है।

भले ही एनसीईआरटी के डायरेक्टर इससे इंकार करते रहें, एनसीईआरटी की पुस्तकों में से चुनिंदा अध्यायों/हिस्सों, जो वर्तमान सरकार की व्यापक विचारधारात्मक उन्मुखता के लिए उपयुक्त नहीं हैं, को हटाए जाने से स्कूल पाठ्य–पुस्तकों में संशोधन के जरिये इस सरकार के गैर–एकेडेमिक एवं विभाजनकारी एजेंडे का पर्दाफाश होता है।

वर्तमान सरकार इस विचारधारात्मक एजेंडे पर काम कर रही कि भारत के इतिहास को इस तरह पेश किया जाए कि वह आधिपात्यपूर्ण एकल (हिन्दू) परंपराओं से बना है। पाठ्य–पुस्तकों में से चुनिंदा विषयों के हटाए जाने का गहराई से विश्लेषण करने पर यह बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाता है कि ये बदलाव इतिहास के इस प्रकार विकृतीकरण के उसके विचारधारात्मक एजेंडे की पृष्ठभूमि में किए गए हैं।

इस तरह एजेंडे से प्रेरित होकर, इतिहास पाठ्य पुस्तक के खंड 2 से ''राजा और इतिवृत्त'' शीर्षक अध्याय से, मुगल दरबार (16वीं–17वीं शताब्दी) को हटा दिया गया है। मुगलों ने उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर काफी लंबी अवधि तक राज किया, जिससे उस समय का इतिहास उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया। इसके बावजूद यह अध्याय हटा दिया गया है। मध्यकालीन दौर में, मुगल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। पिछली पाठ्य–पुस्तकों में इन दोनों साम्राज्यों की चर्चा थी। पुस्तकों के संशोधित संस्करण में मुगलों के संबंध में जो अध्याय था उसे हटा दिया गया है और विजयनगर साम्राज्य के संबंध में जो अध्याय था उसे पुस्तक में रखा गया है। मुगलों से संबंधित अध्याय को हटाए जाने से व्यापकतर सांप्रदायिक इरादों का पर्दाफाश होता है जो भारत के अतीत के संबंध में इस गलत अवधारणा पर आधारित है कि शासकों का धर्म उस समय का प्रधान धर्म था। इस तरह का विचार ''हिन्दू युग'' और ''मुस्लिम युग'' जैसे अत्यंत समस्यात्मक विचार की दिशा में ले जाता है। ऐतिहासिक तौर पर भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण सामाजिक ताने–बाने वाला देश रहा है। आज उस पर इस तरह का गलत वर्गीकरण थोपा जा रहा है।

इसके अलावा आधुनिक भारत के संबंध में अध्याय 3 से दो अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय हटा दिए गए हैं। यह हैं: ''औपनिवेशिक शहर: शहरीकरण, प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर'' और ''विभाजन को समझना: राजनीति, यादगारें, अनुभव''। गांधीजी की हत्या में हिन्दू कट्टरपंथियों की भूमिका के उल्लेख को हटाया जाना भी एक उल्लेखनीय बदलाव है। इतिहास की पाठ्य–पुस्तक के खंड 3 में एक अध्याय है ''महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन''। उसमें नाथूराम गोडसे का उल्लेख ''एक अत्यंत कट्टरपंथी हिन्दू समाचार पत्र का संपादक'' के तौर पर किया गया था जिसे हटा दिया गया है।

यहां इस पर जोर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य–पुस्तकों से जिन अध्यायों को और अंशों को हटाया है वह किसी एकेडेमिक या शिक्षा शास्त्रीय सोच पर आधारित नहीं है बल्कि यह बदलाव आरएसएस–भाजपा की सांप्रदायिक सोच और इतिहास की विकृत समझ और इतिहास के विकृतीकरण की सुविचारित योजना के अनुसार किए गए। अतीत के अध्ययन से किसी काल को हटाए जाने से छात्र वर्तमान समय से अतीत को जोड़ने वाले क्रम को नहीं समझ पाएंगे और वह अतीत और वर्तमान के साथ जुड़ने, अतीत और वर्तमान के बीच तुलना करने के अवसर से वंचित हो जाएंगे और उस विषय की विषयवस्तु के जैविक अंतर्संबंध भंग हो जाएंगे। इसके अलावा, इतिहास की पाठ्य–पुस्तकों से इतिहास के समूचे दौर को हटाए जाने से गलत अवधारणाएं और गलत समझ ही स्थायी चीजें नहीं बन जाएंगी बल्कि यह चीज शासक अभिजात वर्ग के फूटपरस्त सांप्रदायिक एवं जातिवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी। एनसीईआरटी ने पहले जो पुस्तकें और इतिहास पाठ्यक्रम बनाए थे उनका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी समझ प्रदान करना था जहां विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के आदान–प्रदान और उनके बीच मेलजोल का संगम रहा है और जहां विभिन्न समूह एवं नृवंशताएं (एथनिसिटीज) रहती हैं। पुस्तकों में अध्यायों का अनुक्रम छात्रों को इतिहास की कला के संबंधों में पढ़ाने और अतीत के संबंध में विवेचनात्मक समझ एवं विचार विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था। एनसीईआरटी के पुराने पाठ्यक्रम में मुख्य फोकस भारतीय उपमहाद्वीप की मेल–जोल की विरासत और वर्तमान समय की ऐतिहासिक..... .पर था। उस पाठ्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण अंशों को हटा दिया गया है।

कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तकों से अनेक बातों को हटाए जाने के अलावा 11वीं की पाठ्य–पुस्तक से भी औद्योगिक क्रांति जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को हटा दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य–पुस्तकों से भी अनेक बातें हटा दी गई है जिनमें शामिल हैं: जन आंदोलनों का उभार, 2002 के गुजरात दंगे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख। इसी प्रकार 11वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, ''अंडरस्टैंडिंग सोसायटी'' से 2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख निकाल दिया गया है।

फूटपरस्त और संकीर्णतावादी एजेंडे से प्रेरित एनसीईआरटी ने स्कूल पाठ्य–पुस्तकों से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को चुनिंदा तरीके से निकाल दिया है। इससे न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की मेल–जोल की विरासत को भारी नुकसान पहुंचता है बल्कि यह भारत के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात है। औपनिवेशिक अवधारणाओं और उन्हें आज के समय फिर से पेश करने से भारतीय इतिहास की ऐसी अवधारणा बनती है कि भारतीय सभ्यता एक वर्चस्ववादी एकल परंपरा का उत्पाद है और इस प्रकार ''हिन्दू समाज'' जैसी कैटेगरियों को बिना सोचे–समझे ऐसे देश पर थोपा जा रहा है जहां पर ऐतिहासिक तौर पर एक अत्यंत विविधतापूर्ण सामाजिक तानाबाना रहा है। अंतत, इन तमाम बातों को हटाए जाने से छात्रों के सामने भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही प्रकार के ''हिन्दू समाज'' का एक ऐसा इतिहास पेश हो जाएगा जिसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी गई है और जिसके नापसंद हिस्सों को काट–छांटकर निकाल दिया गया है। इस किस्म का इतिहास राजाओं और वे लड़ाइयां जो उन्होंने लड़ी उन्हीं के संबंध में उलझकर रह जाएगा। इससे राज्य गठन, साम्राज्य निर्माण और मध्यकालीन दौर का रूपातंरण कथित तौर पर '' हिन्दू'' समाज और ''मुसलमान'' हमलावरों और शासकों के बीच निराधार स्थायी लड़ाई–झगड़े के तौर पर हो जाता है। यह चीज भारत के अतीत .में संभाव्यत: व्यापक सामाजिक भाईचारे के विचार को प्रोजेक्ट करती है और शासकों द्वारा लिंग, जाति एवं वर्ग आदि की धुरी के साथ किए जाने वाले शोषण एवं उत्पीड़न को छिपाती है। यह चीज क्षेत्रीय विभिन्नता को भी नजरअंदाज करती है। इतिहास के अध्ययन को इस तरह के एकाश्मक विवरणों के रूप में घटाकर मिथ्या इतिहासों, खासतौर पर साप्रंदायिक एवं जातिवादी इतिहासों को हावी बनाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। बहरहाल, इस तरह के ''इतिहासों को आजकल वाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया एप्लीकेशनों के जरिये बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है।

इतिहास की पुस्तकों से अध्यायों एवं हिस्सों को निकालने के एनसीईआरटी के फैसले से हम स्तब्ध एवं चिंतित हैं। हम मांग करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में किए गए इन बदलावों को तुरंत वापस लिया जाए। एनसीईआरटी का फैसला फूटपरस्त उद्देश्यों से प्रेरित है। यह फैसला भारतीय उपमहाद्वीप के संवैधानिक लोकाचार और मेलजोल की संस्कृति के खिलाफ है। अत: इसे शीघ्रातिशीघ्र वापस लिया जाए।

जिन इतिहासकारों ने इस बयान को जारी किया है उनमें आदित्य मुखर्जी, अनामिका, आनन्द के. सहाय, अनुराधा रॉय, आशिक अहमद इकबाल, दिलीप मेनन, दिनेश वार्ष्णेय, हरबंस मुख्या, इन्द्राणी दत्ता, इरफान हबीब, जयति घोष, ए.एन.सुनन्दन, काली चित्ती बाबू, एम.एच. इलियास, मनोरमा शर्मा, माया जॉन, मृदुला मुखर्जी, मुकुल केशवन, नंदिता नारायण, प्रतीक दत्ता, प्रणव कांति बसु, आर.एस. मीणा, रणवीर चक्रवर्ती, रवि आहूजा, रोमिला थापर, एस.के.एहतशानुद्दीन अहमद, एस.कृष्णा स्वामी, शांतनु सेनगुप्ता, सारा चौहान, शादाब बानो, शिवजी के. पणिक्कर, सुभेन्दु दासगुप्ता, सुचेता महाजन, सुजाता पटेल, सैयद अली नदीम रिजवी, तिलक हजारिका, तिलोत्तमा मुखर्जी, वीरेन्द्र सिंह, युसुफ सईद आदि शामिल हैं।

शाहबाद के शहीदों को भाकपा पानीपत ने याद किया

पानीपत, 9 अप्रैल 2023: स्थानीय भगत सिंह स्मारक, कामरेड टीका राम सखुन हाल सभागार पानीपत में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने शाहबाद के शहीदों–खुशदेव सिंह, गुरप्रीत कौर, गुरदीप सिंह–को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सैंकड़ों उपस्थित साथियों ने गगन भेदी नारे.... शाहबाद के शहीदों को लाल सलाम, ...शहीद खुशदेवसिंह, गुरप्रीत कौर व गुरदीप सिंह अमर रहें....ना हिन्दुराज ना खालिस्तान जुग जुग जिए हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान के बीच शानदार यादगार सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता जमशेद राणा, अशोक पंवार, पृथ्वी सिंह सैनी व सेवा सिंह मलिक ने की।

सभा का मंच संचालन राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला सचिव पवन कुमार सैनी एडवोकेट ने किया व अपने सम्बोधन में उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 1988 को खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने शाहबाद के तत्कालीन सीपीआई विधायक डॉ. हरनाम सिंह के घर पर स्वचालित हथियारों के साथ जानलेवा हमला कर दिया था। जो इस हमले का निहत्थे होकर खुशदेव सिंह एडवोकेट, गुरप्रीत कौर, गुरदीप सिंह, डाक्टर हरनाम सिंह व माता जसवंत कौर सभी ने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। यह भारत वर्ष मे पहली घटना थी कि जबत्र इस परिवार ने आतंकवादियों का जबरदस्त विरोध व मुकाबला करते हुए एक आतंकवादी को वीरांगना माता जसवंत कौर ने दबौच लिया था। इस आतंकवादी हमले में डॉक्टर हरनाम सिंह के बेटे एडवोकेट खुशदेव सिंह, पुत्रवधु गुरप्रीत कौर एवं निकट सम्बंधी गुरदीप सिंह शहीद हो गए और डॉ. हरनाम सिंह, उनकी पत्नी जसवंत कौर गम्भीर रुप से घायल हो गये थे। तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम के आर नारायणन ने इस परिवार के पांच सदस्यों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था।

सभा मे शामिल सभी साथियों ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। जमशेद राणा, अशोक पंवार व सेवा सिंह मलिक ने शाहबाद के शहीदों को याद करते हुए कहा कि इन शहीदों ने ''न हिन्दु राज ना खालिस्तान, जुग जुग जुग जिए हिन्दुस्तान'' का नारा लगाते हुए देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये थे। सीपीआई के जिला सचिव पवन कुमार सैनी ने कहा कि आज फासीवादी सम्प्रदायिक ताकतें सत्ता में बैठ कर देश में जातिवाद व धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं तथा राष्ट्रीय व सार्वजनिक संस्थानो को बेच कर कारपोरेट घरानों को पाल रही हैं। आज देश में मजदूरों, किसानों सहित सभी मेहनतकश जनता की एकता के लिए प्रयास करना ही शाहबाद के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर कृष्ण लाल सैनी, मांगे राम सैनी,सतीश कुमार, ओम सिंह यादव, भूपेन्द्र कश्यप, नवल किशोर, राम कुमार सैनी, जुनैद राणा, रूपेश सैनी, सोनू सैनी, जोगिंदर सिंह, संजय तंवर, प्रदीप जिंदल,महबूब आदि ने शहीदों को नमन किया।

ओड़ीशा राज्य स्तरीय विकल्प समावेश

सांप्रदयिक फासीवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष का आह्वान

रमेश पाधी

भुवनेश्वरः 23 मार्च 2023 को भगत सिंह के शहादत दिवस पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार की सांप्रदायिक फासीवादी, लोकतंत्र विरोधी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और ओड़ीशा सरकार के कुशासन और नए ओड़ीशा के गठन के लिए 18 सूत्री वैकल्पिक कार्यक्रम के तहत भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय विकल्प संवाद का आयोजन किया।

रैली के लिए भाकपा कार्यकर्ता, जन संगठन के सदस्य और समर्थक हजारों की संख्या में राज महल स्क्वेर पर लालझंडों, बैनरों, तख्तियों के साथ इकट्ठे हुए। वहां से वे रैली में मास्टर कैंटीन स्क्वेर होते हुए ओड़ीशा विधानसभा के सामने लोअर पीएमजी पर बनाए गए विकल्प समावेश स्थल पर पहुंचे। रैली में मोदी सरकार के सांप्रदायिक फासीवादी एजेंडे और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाए गए। भाकपा के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डा. भालचंद्र कांगो ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कॉर्पोरेट घरानों के हितों की सेवा कर रही है, संसद में घटी हाल की घटनाएं इसका सबूत है। अडानी घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग से बचने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा योजनाबद्ध तरीके से संसद की कार्यवाही को रोक रही है। नरेंद्र मोदी के इस 9 साल के शासन में भूखों की संख्या 35 करोड़ तक पहुंच गई है। मोदी सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की धुन पर थिरकते हुए घरेलू और विदेशी पूंजीपतियों को सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियां सौंप रही है। विदेशी पूंजीपति देश के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं यह राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय संसद में एकपक्षीय तरीके से काले कृषि कानून पारित किए गए और दिल्ली बॉर्डर पर काले कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग पर किसानों द्वारा साल भर चलाए गए आंदोलन से मजबूर होकर सरकार को ये काले कानून वापिस लेने पड़े, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दी।

डा. कांगो ने कहा कि मोदी जी ने सालाना 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन 4 करोड़ श्रमिकों और कर्मचारियों ने अपनी नौकरी और रोजगार खो दिए। मोदी सरकार पर आरएसएस का नियंत्रण है जो कि फासिस्ट विचारधारा को चला रही है। सरकार के सहयोग से ये फासीवादी ताकतें देश भर में नफरत और वैमनस्य के बीज बो रही हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रही है। इन सब के विरुद्ध देश की सभी वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। खीरोद प्रसाद सिंहदेव ने विकल्प समावेश के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बैठक में आरंभिक भाषण दिया। पूर्व भाकपा विधायक नारायण रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। भाकपा ओड़ीशा राज्य सचिव अभय साहू ने इस अवसर पर बोलते हुए शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने फांसी दी थी। उन्होंने कहा कि ओड़ीशा प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से समृद्ध है लेकिन ओड़ीशा एक गरीब राज्य के रूप में पीड़ित है। राज्य के किसान हफ्तों तक मंडियों में अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। रोजगार और नौकरी की तलाश में प्रदेश के लाखों युवा बाहर जा रहे हैं। ओड़ीशा में आज एक भी वस्तु उत्पादित करने वाला उद्योग नहीं है। पहले जो भी कुछ उद्योग काम कर रहे थे, वे फिलहाल बंद हैं। राज्य सरकार उद्योग का अर्थ केवल इस्पात उद्योग है। काली सूची में शामिल पोस्को को लोगों के मजबूत विरोध आंदोलन के कारण ओड़ीशा छोड़ना पड़ा। पोस्को के वहां से चले जाने के बाद एक और कंपनी को जबरन स्थापित किया गया है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने क्रूर अत्याचार किए। ओड़ीशा में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। ओड़ीशा में राज्य के कैबिनेट मंत्री को भी एक पुलिस कार्यालय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पीटा। ओड़ीशा में महिलाओं, बच्चों, दलितों और जनजातीय लोगों पर अत्याचार और आपराधिक धमकी के मामले में राज्य को नंबर एक श्रेणी में रखा गया है। लोगों के जीवन और आजीविका का ह्रास हुआ है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य को बदलने के लिए और ओड़ीशा के नए गठन के लिए भाकपा 18 सूत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के साथ इस विकल्प समावेश का आयोजन कर रही है। उन्होंने सभी वाम, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से केंद्र में सांप्रदायिक फासीवादी भाजपा सरकार को हराने के लिए एकजुट होने और नए ओड़ीशा के गठन के लिए इस वैकल्पिक कार्यक्रम का समर्थन करने की अपील की। भाकपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आशीष कानुनगो, राज्य सचिवालय के सदस्य डा. प्रशांत मिश्रा, आशिक दास, प्रशांत पटटूजोशी, जयंत दास, प्रकाश पात्रा और पूर्व राज्य सचिव दिबाकर नायक ने अपने संबोधन में कहा कि विकास के नाम पर ओड़ीशा में बड़ी लूट हो रही है। बीजद सरकार के निश्चेतन रवैये के कारण सांप्रदायिक ताकतें राज्य में अपना तमाशा फैला रही हैं। ओड़ीशा में भाजपा और बीजद के बीच अलिखित समझौता है। बीजद ने संसद में जम्मू–कश्मीर में 370 हटाने, काले कृषि कानूनों और श्रमिक विरोधी 4 श्रम संहिता जैसे सभी जनविरोधी नीतियों और विधेयकों को समर्थन दिया है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वे नकली लड़ाई में लगे हुए हैं। इसलिए भाकपा ने भाजपा हटाओ, देश बचाओ आंदोलन का और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों को हटाने का आह्वान किया है।

एटक राज्य सचिव विजय जेना, उत्कल महिला समिति महासचिव जिनमयी साहनी, बीकेएमयू राज्य सचिव सुरा जेना, एआईवाईएफ राज्य सचिव प्रदीप सेठी और एआईएसएफ राज्य सचिव संघमित्र जेना ने भी इस मौके पर सभा को संबोधित किया और राज्य में लोगों द्वरा भोगी जा रही कई समस्याओं पर ध्यान दिलाया और देश एवं राज्य को बचाने के लिए सभी वाम, जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के संयुक्त संघर्ष का आह्वान किया। रैली जिन 18 बिन्दु वैकल्पिक कार्यक्रम की मांग के लिए की गई थे वे मांगें हैंः धान का मूल्य तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए; बंटाईधारों को मान्यता दी जाए; राज्य के हर एक खंड में कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाएं; सभी खेती की जमीनों के लिए सिंचाई की सुविधाएं; राज्य में वस्तु, वन और कृषि आधारित उद्योगों को लगाकर रोजगार तैयार किए जाएं; दस्तकारों को प्रोत्साहन; 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए; सभी नवयुवकों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता; सभी रोजगारों और सरकारी नौकरियों से संविदा चलन को हटाया जाए; सभी रिक्त पड़े सरकारी पदों को भर जाए; स्कीम वर्कर्स को शासकीय सेवक की मान्यता और प्रति माह 25000 वेतन मिले; शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण बंद हो; खेत मजदूरों को साल भर रोजगार मिले; मनरेगा वर्कर की प्रति दिन दिहाड़ी 700 रुपये हो; 55 साल के प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5000 हजार रुपये पेन्सनय महिलाओं पर अत्याचार बंद हों और सभी महिलाओं को समान अवसर मिले; दलित और आदिवासियों पर अत्याचार बंद हों; आदिवासियों को वन और वन उपज संग्रह का अधिकार; भूमिहीन गरीबों को जमीन पट्टा मिले; चिट फंड जमाकर्ताओं का धन वापिस करो; मजदूर विरोधी 4 श्रम कानूनों को रद्द करो और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को वापिस लो; मूल्य वृद्धि नियंत्रण के सख्त उपाय और ग्रीन कार्ड धारकों को प्रति माह एक हजार रुपये दिए जाएं।

मुखिया महासंघ ने विभिन्न मांगों के समर्थन में दिया महाधरना

दरभंगा, 8 अप्रैल 2023: दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष व सीपीआई के सहायक जिलामंत्री राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिले के मुखियाओं ने पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर महाधरना दिया।

जिसमें वक्ताओं ने कहा कि पंचायत सरकार को लगातार सरकार एवं प्रशासन द्वारा कमजोर करने की साजिश चल रही है। गांधीजी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। पंचायत सरकार बनेगी तो आमजन आमसभा के माध्यम से गांव के विकास का फैसला खुद करेगा। मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट–2 में निविदा के माध्यम से पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा पंचायतों में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्यकारी एजेंसी का चयन कर लिया गया है जो गलत है और जिले में कोई भी राजस्थानी एजेंसी पंचायतों के संपर्क में नहीं है और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा पंचायत सेवकों को डराकर प्रशासनिक स्वीकृति पंचायतों से लाकर अपने पास रखी जा रही है जबकि पंचायत का दस्तावेज पंचायतों में रहना चाहिए और कार्यकारी एजेंसियों को पंचायतों में एकारनामा करना चाहिए।

विगत चुनाव के बाद से अनेको पंचायतों में जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला हो रहा है। मनरेगा मजदूर 210 रूपया पर मनरेगा मापदंड के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं जिससे मनरेगा से कार्य करवाने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। कई प्रखंडों में 15वीं एवं अन्य योजनाओं का प्रशासनिक दस्तावेज लेकर बीपीआरओ प्रखंड बुलाते हैं और आर्थिक दोहन करते हैं तथा कहते हैं कि एमबी हमसे रिलीज करा कर ले जाओ। पंचायत स्तरीय कर्मी अक्सर पंचायतों में नहीं रहते हैं एवं पूछने पर बताते हैं कि मेरा प्रतिनियुक्ति प्रखंड एवं जिले में है। वक्ताओं ने कहा कि आज के महाधरने के द्वारा सरकार से हम मांग करते हैं कि पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाले एजेंसी को पंचायतों में आकर एकारनामा करने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के देखरेख में करवाया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा की गारंटी की जाए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए मनरेगा मजदूरी कम से कम 500 रू. की जाए। पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन में कुछ प्रखंडों के बीपीआरओ द्वारा जबरन एमबी निर्गत करने का दबाब बंद करवाया जाए। कम से कम सप्ताह में 1 दिन पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायत के समस्याओं के निदान हेतु पदाधिकारी मिलने का समय निर्धारित करें। पंचायत स्तरीय कर्मियों को पंचायत कार्यालय में उपस्थित पंजीकृत पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कराया जाए। पंचायत को संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप सभी अधिकार दिया जाए। कार्यपालक सहायकों को सभी स्तर का लॉगिन पासवर्ड दिया जाए। जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड निर्माण में बिचौलियों को चिन्हित कर कार्रवाई हो और प्रणाली बिचौलियों मुक्त हो। पंचायतों में पंचायतों के अतिरिक्त किसी विभाग का योजनाओं के कराने के लिए पंचायतों से एनओसी लेना अनिवार्य किया जाए आदि हैं।

महाधरने के मौके पर जिलाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी से सकारात्मक वार्ता हुई तदुपरांत धरने को समाप्त किया गया एवं मुखिया महासंघ के द्वारा कहा गया कि हमारी मांगों पर जिला प्रशासन सकारात्मक कार्य नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने हेतु विवश होंगे। मौके पर धरने को हरी भूषण प्रसाद यादव अध्यक्ष सदर, इत्तेफाक अहमद अध्यक्ष केवटी, श्यामनंदन यादव अध्यक्ष बहादुरपुर, राजकुमार चौधरी अध्यक्ष हायाघाट, आभा देवी, चंदेश्वर झा, चन्द्रवती देवी, अहमद अली तमन्ने, अंजनी कुमार झा संरक्षक, सुरेंद्र यादव अध्यक्ष बहेरी, पप्पू चौधरी अध्यक्ष सिंहवाड़ा, आभा देवी, चंद्रकला देवी आदि ने संबोधित किया।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ

पटना

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे राज्य में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जयंती मनाएगी और संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेगी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद मोदी की सरकार संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। इस सरकार में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हमले बढ़े हैं। संविधान को समाप्त कर देश पर नागपुर से संचालित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संविधान देश पर थोपा जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जयंती पूरे राज्य में धूमधाम से मनाते हुए भाजपा हटाओ–देश बचाओ राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान के तहत बाबा डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल से 15 मई तक गांव–गांव पदयात्रा निकालेगी। भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि मोदी सरकार में देश में लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को रौंदा जा रहा है। मोदी सरकार का जो विरोध करता है, उसके पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी भाजपा में चले जाते हैं, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

सरकारी सम्पतियों को कौड़ी के भाव में पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गरीब मजदूर किसान विरोधी तथा कॉरपोरेट पक्षी नीतियों के खिलाफ डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जयंती के मौके राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आंदोलन की शंखनाद किया जाएगा।

लखीसराय

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला परिषद लखीसराय की बैठक रामपदारथ सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

परिषद को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत गम्भीर है। देश में भ्रष्टाचार, कमरतोड़ महगाई, करोड़ों बेरोजगारी, गरीब लड़कों की मुश्किल में पड़ी शिक्षा, मंहगी चिकित्सा व्यवस्था आदि सवाल देश को संकट में डाल दिया है।

राम नरेश पांडेय ने कहा कि देश की ज्वलंत सवालों पर संसद में बहस के बजाय भाजपा ने खुद 'राहुल गांधी, मांफी मांगो' का नारा लगाते हुए संसद वाधित रखी।

राज्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी ने केंद्र सरकार को हटाने के लिए बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर और भाकपा के पूर्व महासचिव पी. सी. जोशी की जयंती 14 अप्रैल से 15 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ' नारे के तहत अभियान शुरू करने जा रही है। इन्होंने कहा कि 8–9 जून को बिहार में जन सत्याग्रह के तहत हम 'जेल भरो अभियान' चलाएंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 2 नवम्बर को पटना में पार्टी की विशाल रैली होगी।

बैठक को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी पूर्व राज्य सचिव व विधायक राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने विस्तार से भावी आंदोलनों की चर्चा की।

बैठक में राज्य कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र कुमार, पूर्व प्राचार्य प्रो. विजयेंद्र प्र. सिंह, अरुण कुमार सिंह, विश्वरंजन, चन्द्रशेखर, कैलाश, द्वारिका प्र. विंद, महिला समाज की नेत्री रिंकू कुमारी, शहनाज, श्रीराम भगत, यूथ फेडेरेधन के रंजीत पासवान और धनंजय कुमार, अर्जुन विंद, प्रमोद यादव आदि उपस्थित थे।

बैठक में आंदोलनों की रूपरेखा जिला सचिव हर्षित यादव ने रखी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अंचल मुख्यालयों पर बाबासाहेब की जयंती मनाई जाएगी। साथ ही जेल भरो अभियान को लक्ष्य रख अंचलों में पदयात्रा, कोष और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान भी होगा, जिसे सबकी सहमति से पारित किया गया।

ग्वालियर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देशव्यापी भाजपा हटाओ–देश बचाओ–संविधान बचाओ नारे के साथ पूरे देशभर में 14 अप्रैल से 15 मई 2023 पदयात्रा करना तय किया गया है। जिसके तहत जिला ग्वालियर पार्टी ने भी जिले में पदयात्रा करने का निर्णय भाकपा जिला परिषद द्वारा लिया गया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला ग्वालियर सह सचिव एवं मध्यप्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य कौशल शर्मा ने बयान जारी कर बताया कि बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक नफरत के विभाजन की राजनीति के खिलाफ तथा अडानी, मोदी के आर्थिक घोटालों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर 14 अप्रैल से पार्टी द्वारा पदयात्रा प्रारंभ की जा रही है। जिसके तहत 14 अप्रैल 2023 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्वालियर के सभी कार्यकर्ता छपर वाला पुल लश्कर ग्वालियर पर प्रातः 9.00 बजे इकट्ठा होकर पदयात्रा प्रारंभ कर, अंबेडकर स्मारक फूलबाग पर पहुंचकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविधान के खिलाफ कार्य कर देश में प्रायोजित सांप्रदायिक नफरत के विभाजन की राजनीति एवं धार्मिक उन्माद एवं जातिगत द्वेष का विरोध करते हुए बाबा अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के अनुरूप सरकार कार्य करे, इसका आहवान करेंगे। साथ ही बाबासाहेब अंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण कर जन जागरण करने की शपथ ली जायेगी।

पदयात्रा के इसी क्रम में 16 अप्रैल 2023 को सरवटे भवन हजीरा ग्वालियर से दोपहर 4 बजे पार्टी कार्यकर्ता पदयात्रा कर हजीरा चौराहा होते हुए ग्वालियर सर्राफा बाजार होते हुए किला गेट चौराहे पर पदयात्रा समापन करेंगे। पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पार्टी के नेतागण कौशल शर्मा, अशोक पाठक, हरिशंकर माहौर, शैलेश परमार, अनवर खान, रमेश सविता, प्रकाश वर्मा, अब्दुल शाहिद, अंजलि परमार, ज्ञान देवी वर्मा, सुमन कुशवाह, रामभरोसे जैन, जालिम सिंह, प्रीतम सिंह माहौर ने सभी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में और समय पर भाग लेने का अनुरोध किया।

गाजीपुर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रांच कमेटी सिहोरी की बैठक स्थानीय कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई।

इसे सम्बोधित करते हुए पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव ने कहा कि आज संविधान, लोकतंत्र, सांप्रदायिक सौहार्द, आजादी आंदोलन की उच्चतम उपलब्धियां गंभीर खतरे में हैं। यह संकट वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से है। संविधान के मूल ढांचे पर चोट की जा रही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की अवहेलना की जा रही है। असहमति के स्वर को कुचला जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई से बने खजाने को अडानी और उनके सरीखे पूंजीपतियों को निरंकुशता के साथ सौपा जा रहा है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तबाह हो रहे हैं। महंगाई,बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश के अन्य सवालों पर संसद में सत्तापक्ष द्वारा चर्चा ही नहीं होने दी जा रही है। प्रतिपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का सहारा लिया जा रहा है। ईडी, सीबीआई को तो पूछना ही नहीं। सरकार एकदम से तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। सत्ता मे बने रहने के लिए लगातार विभाजनकारी नीति का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना समय का तकाजा है। भाकपा राष्ट्रीय पैमाने पर 14 अप्रैल से 15 मई तक पदयात्रा एवं जनसभा का कार्यक्रम करेगी। इसकी व्यापक तैयारी करनी होगी।

बैठक में ब्लॉक मंत्री बच्चेलाल ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर जनता का उत्पीड़न हो रहा है। इससे पार पाने के लिए जनता की व्यापक लामबंदी आवश्यक है। इसमें ब्रांचमंत्री राजेंद्र खरवार, कन्हैया गोंड, जुम्मादीन, रजनीश कुमार भारती, समसुद्दीन, पारस राम, विष्णु नारायण आदि ने अपने विचार प्रकट किये। बैठक ने नंदगंज सिहोरी शुगर मिल चालू करने की जोरदार मांग सरकार से की। साथ ही विकास केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने,पुलिस द्वारा उत्पीड़ितों का शोषण बंद करने की मांग जिला प्रशासन से की गई। सभा की अध्यक्षता राम मनोहर मास्टर ने की।

सिरसा

भाकपा जन मुद्दों को लेकर हरियाणा में 1 मई से 15 मई तक राजनीतिक जन जागरण अभियान चलाएगी। यह निर्णय आज स्थानीय सेठ तुलाराम धर्मशाला में सम्पन्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कौंसिल की एक मीटिंग में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सीपीआई के वरिष्ठ नेता स्वर्ण सिंह विर्क ने की और पार्टी के राज्य सह सचिव तिलक राज विनायक ने पार्टी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने गत दिवस पुडुचेरी में सम्पन्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नैशनल कौंसिल की मीटिंग में लिये गए फैसलों की जानकारी दी।

दरियाव सिंह कश्यप ने कहा कि सीपीआई की स्पष्ट समझ है कि केन्द्र और हमारे राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी बढी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा नेताओं के घरों में करोड़ों–करोडों रुपयों की नगदी मिल रही है लेकिन ईडी और दूसरी एजेंसियां विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे मार रही है।

उन्होंने ने कहा कि मजदूरों, किसानों गरीबों के मुद्दों तथा देश में लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए सीपीआई ने 14 अप्रैल से 15 मई तक देशभर में पदयात्रा कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है।

बैठक में इस फैसले की रोशनी में हरियाणा में 1 मई से 15 मई तक राजनीतिक अभियान चलाने का फैसला किया गया। इस दौरान भाजपा सरकार की जनविरोधी, देशविरोधी, संविधान विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनरेगा एवं अन्य सामाजिक कार्यो के लिए आवंटित राशि बढाने, शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं को रोजगार देने आदि ज्वलंत सवालों को लेकर भारी संख्या में सभाएं, नुक्कड मीटिंग की जायेंगी। इस दौरान सीपीआई के गौरवशाली इतिहास से आम जनमानस को अवगत कराया जायेगा। बैठक में राज्य में विशेष फंड संग्रह अभियान चलाने और 31 मई तक पार्टी के नये सदस्य बनाने का फैसला किया गया। बैठक में राज्य में हो रही बेमौसमी बरसात से भारी मात्रा में गेहूँ, सरसों, सब्जी, हरे चारे की फसल नष्ट पर दुख व्यक्त किया गया और सभी खराब हुई फसल पर कम से कम प्रति एकड़ 25 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग की गई।

बैठक में तिलक राज विनायक, सत्येन्द्र गिरि, अश्वनी कुमार बक्शी एडवोकेट, रुप सिंह, पवन कुमार सैनी एडवोकेट, मनीराम, राम रतन एडवोकेट, प्रेम सिंह,, हरभजन सिंह विर्क, जगरुप सिंह, माम चंद सैनी, प्रीतपाल सिद्धू, महेन्द्र सिंह तंवर, जमशेद राणा, रामेश्वर पाल आदि ने विचार विमर्श में भाग लिया।

हैदराबाद में भाकपा और भाकपा (मा) की संयुक्त जन...

पेज 1 से जारी...

इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के हाथों हारी। दिल्ली नगरनिगम में भाजपा पिछले 15 साल से सत्ता में थी, परंतु पिछले दिनों हुए चुनाव में उसे आम आदमी पार्टी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा केवल गुजरात के चुनाव जीत सकी है। इन तथ्यों को आम लोगों की जानकारी में लाया जाना चाहिए। इन चुनावों में भाजपा को इस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा फिर भी मीडिया शेखी बघारता रहता है कि आगामी चुनाव में भाजपा सत्ता में आएगी। इसका अर्थ है कि ईडी और सीबीआई की मदद से और धन–बल की ताकत से भाजपा दल बदलने को प्रोत्साहन देगी और अन्य पार्टियों के विधायक तोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि गोवा, मध्यप्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में उसने दल–बदल कराकर सरकारें बनाई।

भाकपा (मा) महासचिव ने आगे कहा कि किसी ने मोदी से सवाल किया कि त्रिपुरा में दो संसदीय सीटें हैं, उसके चुनाव के लिए आप इतनी अधिक प्राथमिकता क्यों दे रहे है? उनका जवाब था यदि भाजपा जीतती है तो वह कम्युनिस्टों की हार होगी। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ केवल कम्युनिस्ट और लाल झंडे ही लड़ेंगे। भाकपा और भाकपा (मा) मिलकर चुनाव के जरिये लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हराएंगे। लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए हमें सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीतिक एवं विचारधारात्मक संघर्ष जारी रखना चाहिए।

सीताराम येचुरी ने आगे कहा कि तेलंगाना में हमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अपने साथ लेना चाहिए। यह एक दशक में पहली बार हुआ है कि भाकपा और भाकपा (मा) के बीच जमीनी स्तर से एकता आई है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां गौरवपूर्ण तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष की विरासत हमारे पास है, यदि हम उस गौरव को बहाल करना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिस्टों के बीच एकता आवश्यक एवं अपरिहार्य है। भाकपा और भाकपा (मा) की तेलंगाना इकाईयों ने जो कदम आगे बढ़ाया है उससे हमें एक नया रास्ता मिल सकता है। दोनों राज्यों के नेताओं ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर भी विचार–विमर्श किया जाएगा। भाजपा को हराने के लिए हरेक राज्य में वहां के राजनीतिक हालात के अनुसार एक कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए। इस संबंध में वामपंथी पार्टियों के ऊपर कहीं अधिक जिम्मेदारी है।

येचुरी ने कहा कि अतीत में क्या हुआ उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अपने साथ लेना चाहिए। हमारी एकता भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि भाजपा को हराना। यदि तेलंगाना में वामपंथी पार्टियां इस लक्ष्य को हासिल करती है तो वह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा की बात होगी। राज्यों में वहां के वर्तमान हालात के अनुसार पार्टियों को अपने साथ लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा केवल चुनावों के बाद बनेगा। उन्होंने याद दिलाया कि 1996 और 2004 में युनाइटिड फ्रंट और यूपीए का गठन चुनावों के बाद ही हुआ था। उन्होंने कहा कि 2004 में वामपंथी पार्टियों ने संसद की 61 सीटों पर जीत पाई थी और 75 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस को हराया था। इसके बावजूद लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने के लिए हमने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया।

अपनी हाल की तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह राज्य का विकास करना चाहते हैं परंतु तेलंगाना सरकार रोक रही है। मोदी इस तरह बात कर रहे हैं मानो वह अपना स्वयं का पैसा खर्च कर रहे हैं। येचुरी ने कहा कि जिन राज्यों में गैर–भाजपा सरकार है, मोदी सरकार उनसे राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकर छीन रही है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर वह गैर–भाजपा सरकारों को अस्थिर कर रही है। ईडी ने पांच हजार मामले दर्ज किए हैं लेकिन केवल 0.5 प्रतिशत मामलों में ही आरोप साबित कर पाई। इसका अर्थ है कि फर्जी मुकदमे कायम कर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और संघवाद की भावना को नुकसान पहुंचा रही है। मोदी सरकार ने पिछले सात सालों में पूंजीपति वर्ग के ऊपर बकाया 11 लाख करोड़ रुपए के ऋणों को बट्टेखाते में डाल दिया है परंतु वह किसानों के ऊपर बकाया ऋणों के मामले में ऐसी रहमदिली नहीं अपनाती।

येचुरी ने आगे कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के फलस्वरूप देश में असमानता बढ़ रही है; अमरी और अधिक अमीर हो रहे हैं, गरीब और और अधिक गरीब हो रहे हैं, महामारी की अवधि में देश के चंद लोगों के हाथ में देश की अधिकाधिक धन–दौलत पहले के मुकाबले कहीं अधिक संकेंद्रित हो गई। मोदी राज में आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं रही। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 से बढ़कर 1100 रु. से अधिक हो गई है। लोगों का ध्यान इन समस्याओं से हटाने के लिए भाजपा देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। पिछले दो साल में हमने देखा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया है। संसद में कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

आम सभा के समापन पर भाकपा नेता अब्बास ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। सभा के दौरान दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह देखा गया। इप्टा और प्रजा नाट्य मंडली की टीमों ने क्रांतिकारी गीतों से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर डी. राजा और सीताराम येचुरी ने बी.एस. रामबाबू द्वारा तैयार की गई एक सीडी ''लाल झंडे एकताबद्ध हों'' का विमोचन किया। डॉ. के. नारायणा और बी.वी. राघवुलु ने प्रगतिशील लेखक संघ के लेखकों और कवियों द्वारा लिखित सांप्रदायिकता के विरूद्ध एक पुस्तक का विमोचन किया ।

सरकार के बगैर ड्रोन हमला कैसे संभव है: भाकपा

सुकमा। बीजापुर सुकमा की सीमा के नजदीक ग्रामीणों ने शुक्रवार ड्रोन हमले का जो आरोप लगाया था शनिवार को बस्तर इलाके के ग्रामीणों को तस्वीरें दिखाकर ड्रोन हमले की बात भी कही थी। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में शुक्रवार को प्रातः लगभग 6 बजे के आसमान में ड्रोन नुमा एक मशीन से 20–25 गोले फेंके गए। पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इंकार करती रही है ड्रोन हमले को लेकर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मनीष कुंजाम राज्य सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ दिन पहले पामेड़ क्षेत्र के ग्राम जब्बागट्टा, मीनागटटा, काउरगटटा, भट्टीगुडा आदि गांवों में फिर से ड्रोन द्वारा बमबारी करने की खबरें प्रसारित हो रही है, ड्रोन से ही नहीं बल्कि इस बार हैलीकाप्टर से भी प्रातः 05 से 06 बजे के दरम्यान आसमान से बम गिराये गये। महुआ फूल बीनने के साथ ही आदिवासियों सबसे प्रमुख त्योहार (पण्डुम) बीज पण्डुम शुरू हो जाता है। संदेह स्वाभाविक है कि आसमान से बम गिराने से बहुत बड़ी सारकेगुड़ा घटना से भी बड़ी घटना हो सकता है। सवाल यह है कि अभी सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के मौके पर बस्तर में आकर देश के केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा था कि नक्सलवाद काबू में है या नियंत्रण में है, जब नियंत्रण में है तो ऐसे बमबारी की जरूरत क्यों? दूसरा क्या देश के भीतर देशवासियों के ऊपर हवाई हमला नहीं करने का राष्ट्रीय नीति को मोदी सरकार व्दारा बदल दिया गया है? तीसरा यह कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का इस हवाई हमला में क्या भूमिका है? हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन हवाई हमलों की कड़ी निन्दा करती है और मांग करते हैं कि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति न हो।

कामरेड सुरेश धोपेश्वरकर नहीं रहे

बड़े दुख और अफसोस का समाचार है कि बैंककर्मियों के प्रिय नेता कामरेड सुरेश धोपेश्वरकर, पूर्व अध्यक्ष एआईबीईए और पूर्व महासचिव एमएसबीईएफ का शनिवार, 8 अप्रैल, 2023 को 1.45 बजे शुश्रुषा अस्पताल, दादर में निधन हो गया।

शुश्रुषा अस्पताल, दादर में उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर रविवार 9 अप्रैल 2023 को 2 से 5 बजे तक भुपेश गुप्ता भवन, रविन्द्र नाट्य मंदिर के सामने प्रभादेवी में उनके आवास के पास ही अंतिम दर्शनार्थ रखा गया था।

उसके उपरांत 9 अप्रैल को ही शाम के 5 बजे दादर विद्युत श्मशान घाट पर उनके शव को अंतिम संस्कार के लिये ले जाया गया था। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में बैंककर्मियों सहित भाकपा के स्थानीय और राज्य नेताओं ने भी भाग लिया। इसके अलावा उन्हें अंतिम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए भी बडी संख्या में लोग भूपेश भवन पहुंचे थे।

पुन्नी सिंह का साहित्य, प्रेमचंद परंपरा का अग्रगामी विकास है

उपन्यास 'साज कलाई का राग जिंदगी का' विमोचन और परिचर्चा संपन्न

शिकोहाबादः उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की शिकोहाबाद इकाई ने बीते 2 अप्रैल वरिष्ठ कथाकार पुन्नी सिंह के नये उपन्यास 'साज कलाई का राग जिंदगी का' के लोकार्पण और इस पर केन्द्रित एक परिचर्चा का आयोजन रखा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जाने माने समालोचक वीरेन्द्र यादव थे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाटककार राकेश वेदा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि या अन्य वक्ता थे डॉ. महेश आलोक, डॉ. रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर', अरविंद तिवारी, डॉ. विजय, जाहिद खान, अखलाक खान और डॉ. पुनीत कुमार।

शिकोहाबाद स्थित 'द एशियन सी. से.स्कूल' में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों के साथ साहित्यकार और विधार्थी भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत गोरख पांडेय और शैलेन्द्र के जनगीतों के गायन से हुई। उसके बाद अतिथियों ने उपन्यास का विमोचन किया। किताब विमोचन के बाद न सिर्फ उपन्यास 'साज कलाई का राग जिंदगी का' पर विस्तृत बातचीत हुई, बल्कि पुन्नी सिंह के व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान पर भी विचारोत्तेजक चर्चा हुई। प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा दोनों ही संगठनों में उनके योगदान की सम्यक विवेचना की गई। लेखक–पत्रकार जाहिद खान ने पुन्नी सिंह के कथा साहित्य पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''पुन्नी सिंह हिंदी के उन कथाकारों में से एक हैं, जिनके कथा साहित्य में गांव–जोहार बार–बार आता है। किसान–खेतिहर मजदूर, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक पुन्नी सिंह के विपुल कथा साहित्य के केन्द्र बिंदु रहे हैं। उनकी कहानियों में किसानों और आदिवासियों की समस्याएं, उनके सुख–दुख, राग–द्वेष पूरी प्रमाणिकता के साथ उभरकर सामने आए हैं। कहानी 'विस्थापन' और 'उद्घोषणा' में अपनी जमीनों से विस्थापित होते किसानों से लेकर, उनकी कहानी 'मुक्ति' में कर्ज में डूबे किसान का आत्महत्या करने का दृश्य पाठकों को अंदर तक भिगो जाता है।'' उन्होंने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, ''बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश के गांवों का क्या स्वरूप, जातिगत समीकरण, सामाजिक और राजनीतिक माहौल था?, पुन्नी सिंह के 'त्रिया तीन जन्म', 'मंडली', 'सेतुबंध' आदि उपन्यासों को पढ़कर जाना जा सकता है। अपने लोकेल को न सिर्फ वे बहुत अच्छी तरह से आब्जर्व करते हैं, बल्कि उसे प्रमाणिकता के साथ पेश भी करते हैं। हां, उसमें एक विचार साथ–साथ चलता है। वे इससे कहीं विमुख नहीं होते। इसी मायने में वे दीगर रचनाकारों से जुदा हैं।''

लेखक रंगकर्मी डॉ. विजय ने कहा, ''भारत के दलित साहित्य की भूमि के उर्वरा बीज और फिर उसे महाबोधि वृक्ष में बदलने में समर्थ कथाकार पुन्नी सिंह का साहित्य, श्रम के हरकारों को विचार पुरुष बनाने और विचार को श्रम के धरातल पर उतारने का अनुपम उदाहरण है। अपने रचना कर्म में भाषा की सहजता, प्रेमचंद की गहनता, राहुल सांकृत्यायन और आध्यात्म कबीर का लिए, पुन्नी सिंह अपनी कहानी के पात्रों को कल्पना लोक से नहीं, वरन अपने काम करने वाली जगह से बुलाकर, उन्हें अपने विचार की दृष्टि से देखते हैं। और जब यह विचार उनकी रचना शीलता के प्रिज्म से निकलकर पाठक तक पहुंचता है, तो मनुष्यता के संघर्ष का हर रंग उसमें दिखाई देता है। फिर वो चाहे आदिवासी जीवन हो, पिछड़ी और खत्म होती कोई मनुष्य प्रजाति हो, स्त्री, दलित या फिर कोई अकेला मन ही क्यों न हो।'' कवि रंगकर्मी अखलाक खान ने कहा, ''चूड़ियों के मधुर संगीत के साथ जीवन के राग को प्रोफेसर पुन्नी सिंह ने अपने इस उपन्यास में बड़े ही खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। उनके सभी उपन्यास और कहानी संग्रह गहन शोध के बाद सर्जित हुए हैं।

लेखक समीक्षक डॉ. पुनीत कुमार ने कहा, ''पुन्नी सिंह का पूरा साहित्य आम आदमी के संघर्ष और 'विजयी भव' के आर्शीवचनों से भरा पड़ा है। उन्होंने इस इंसानी दुनिया को इंसानों लायक, इंसानों के जरिए ही बनाने का यकीन अपने साहित्य के जरिए जगाने का काम बखूबी किया है।'' कवि, आलोचक डॉ. महेश आलोक ने उपन्यास पर अपनी बात रखते हुए कहा, ''उपन्यास 'साज कलाई का राग जिंदगी का', फिरोजाबाद जनपद के चूड़ी कामगारों के संघर्ष, उनकी अदम्य जिजीविषा और उद्योगपतियों के शोषण–तंत्र को बेनकाब करता है। उन्होंने आगे कहा, ''इस महत्वपूर्ण कृति को यदि हम साहित्यिक यथार्थवाद के खाने में रखकर पड़ताल करेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। असल में यह सिर्फ सामाजिक दृश्य बोध का यथार्थ नहीं है, बल्कि प्रामाणिक अनुभव का संवेदनात्मक यथार्थ है और इसे अभिव्यक्त करने में विश्वसनीयता को कलात्मक संयोग के साथ संयोजित कर दिया गया है। इसलिए यहाँ अनुभव का जीवन्त स्पंदन है, जिसका ध्वनि कंप उपन्यास के समाप्त होने के बाद भी हमारे भीतर लंबे समय तक बना रहता है। यह उपन्यास सिर्फ पॉलीटिकल उपन्यास नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट उपन्यास है।'' परिचर्चा में व्यंग्यकार, उपन्यासकार अरविंद तिवारी और साहित्यकार डॉ. रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' ने भी 'साज कलाई का राग जिंदगी का' पर विस्तृत चर्चा करते हुए इसे महत्वपूर्ण उपन्यास बतलाया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जाने माने प्रगतिशील समालोचक वीरेन्द्र यादव ने कहा, ''पूंजीवाद और निजीकरण की नीतियों से हमारे घरेलू उद्योग आखिरी सांसे गिन रहे हैं। चूड़ी उद्योगभी उसकी गिरफ्त में है। कथाकार पुन्नी सिंह ने अपने नवीनतम उपन्यास 'साज कलाई का, राग जिंदगी का' में इसे कथात्मक दक्षता के साथ दर्ज किया है। आज जब इतिहास का शुद्धिकरण किया जा रहा है और भारतीय समाज को एकरंगी बनाया जा रहा है, तब इस उपन्यास में कम्युनिस्ट लीडर कामरेड सुल्तान बेग और चूड़ी कारीगर नसीर खां समेत कई मुस्लिम पात्रों की जीवंत उपस्थिति से समाज की विविधवर्णी छवि अपने जीवंत रूप में उपस्थित है।'' उन्होंने आगे कहा, ''पुन्नी सिंह का साहित्य प्रेमचंद की परंपरा का अग्रगामी विकास है। पुन्नी सिंह के साहित्य के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी है, लेकिन उसकी केन्द्रीयता और उसका जो विश्लेषण होना चाहिए, उसे आलोचकों के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया जाना चाहिए, वह काम अभी बाकी है। आज के इस आयोजन ने इस कमी को दूर करने की छोटी सी कोशिश की है।'' कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इप्टा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाटककार राकेश वेदा (लखनऊ) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, ''पुन्नी सिंह, प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। जिनके साहित्य में दलित, वंचित, शोषित तबके के पात्र बार बार आते हैं। उनकी प्रतिबद्धता इस तबके के साथ दिखाई देती है।''

कार्यक्रम के दरमियान पूरे समय बीच–बीच में स्थानीय लोगों द्वारा पुन्नी सिंह का शॉल ओढ़ा और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया जाता रहा। जाहिर है कि यह उनके प्रति लोगों के सम्मान और स्नेह को जता रहा था। परिचर्चा उपरांत रायगढ़ इप्टा द्वारा निर्मित पुन्नी सिंह की दो कहानियों 'मुगरा' और 'बच्चे सवाल नहीं करते' पर केंद्रित शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। जिसे सभी ने खूब पसंद किया। उनकी सराहना की। कार्यक्रम के आखिर में पुन्नी सिंह के बेटे वरिष्ठ रंगकर्मी राजेन्द्र यादव ने सभी अतिथियों का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उनका आभार प्रकट किया।

गौरतलब है कि बीसवीं सदी के आठवें नवें दशक के अहम कथाकार पुन्नी सिंह ने विपुल साहित्य लेखन किया है। उनके दस उपन्यास और इतने ही कहानी संग्रह अभी तलक प्रकाशित हो चर्चा में आ चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। आठवें–नवें दशक की कहानी पर केन्द्रित कई चयन में पुन्नी सिंह की कहानियां शामिल हुई हैं। मसलन–'आठवें दशक के लोग', 'काला नवंबर', 'बीसवीं शताब्दी का उत्कृष्ट साहित्य', 'आंचलिक कहानियां खंड–दो', '1993–94 की श्रेष्ठ कहानियां', 'कहानी चयन–1996', 'कथा में गांव', 'जाति दंश की कहानियां' आदि। मध्यप्रदेश सरकार के 'अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार' के अलावा 'मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन' के प्रतिष्ठित 'भवभूति अलंकरण' और उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के प्रतिष्ठित पुरस्कार 'साहित्य भूषण पुरस्कार' से वे नवाजे गए हैं।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी :	70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखेंः
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

सिरसा में भाकपा का चेतना शिविर

सिरसा, 1 अप्रैल 2023: स्थनीय सेठ तुलाराम धर्मशाला में सीपीआई की हरियाणा राज्य कौंसिल की ओर से एक चेतना शिविर आयोजित किया गया। सीपीआई के वरिष्ठ नेता एवं राज्य कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन स्वर्ण सिंह विर्क ने चेतना शिविर का उद्घाटन किया और संचालन सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने किया। चेतना शिविर में प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक, सीपीआई की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अनिल राजिमवाले ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास एवं सीपीआई के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तथा सीपीआई की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी के सदस्य एवं सीपीआई की राज्य शिक्षा सब कमेटी के इंचार्ज अश्वनी कुमार बक्शी ने वर्तमान में बढ़ती सम्प्रदायिकता, फासीवाद की चुनौती और सीपीआई का दायित्व विषय पर विस्तार से चर्चा की।

अनिल राजिमवाले ने कहा कि 1925 में जब से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, पार्टी जनता के बेहतर जीवन के लिए मेहनतकश जनता के संघर्षों की अगली कतार में रही है। उन्होंने कहा कि देश और जनता के लिए बलिदान करने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अन्य किसी भी पार्टी या शक्तियों से पीछे नहीं है। सीपीआई ने देश को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से आजाद कराने में अनेक कुर्बानियां दी और आजादी के बाद देश के विकास के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की संसद और संसद के बाहर अविस्मरणीय भूमिका है। अनिल राजिमवाले ने कहा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराने, देश में भूमि सुधार कराने और भूमिहीनों को जमीन व घर के लिए भूमि दिलाने, समाज सुधार के लिए अनेक योजनाएं एवं कानून बनवाने में अनवरत संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि देश के श्रमिकों, किसानों, मजदूरों के हितों में कानून बनवाने में भाकपा ने संसद और संसद के अनेक योगदान दिया है और हमारी पार्टी का इतिहास सचमुच प्रेरणाप्रद है। अनिल राजिमवाले ने कहा कि आज हमारे देश और कई राज्यों में शासन चला रही भाजपा की सरकार संघर्षों एवं बलिदानों के दम पर प्राप्त किये गए अधिकारों पर हमला कर रही है और देश की सार्वजनिक सम्पत्ति को बडे बडे कारपोरेट घरानों को सौंप रही हैं। उन्होंने सीपीआई कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि भाजपा सरकार व भाजपा की जनविरोधी नीतियों के प्रति जागरण अभियान चला कर जनता को जागरुक करें।

अश्वनी बक्शी ने कहा कि आज हमारा देश एक विशेष राजनीति का सामना कर रहा है, हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा दरपेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के नियंत्रण में चल रही केन्द्र की भाजपा सरकार आम आदमी की परेशानियों को दूर करने के बजाए देश के नागरिकों की एकता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अश्वनी बक्शी ने कहा कि भाजपा–आरएसएस गठजोड़ देश को 80 के दशक की ओर ले जाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने 80 के दशक का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में फूटपरस्त ताकतें देश के टुकड़े करने पर आमादा थी। लेकिन उस समय देश की वामपंथी–विशेषकर सीपीआई के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ''ना हिन्दू राज, ना खालिस्तान–जुग जिए हिन्दुस्तान'' नारा लगाते हुए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने कहा कि आज धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के हमारे गणतंत्र के मुख्य मूल्यों को कुचला जा रहा है। मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत जातीय आधार पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐतिहासिक तौर पर हासिए पर पडे तबकों के साथ भेदभाव चरम पर पहुँच गया है। जाति के नाम पर किसानों, मजदूरों की एकता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, मंदिर, मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दों को भड़का कर हिन्दू राष्ट्र के नारे के पीछे भोले भाले लोगों को लामबंद करके देश की एकता को खतरा पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पुनः कम्युनिस्ट कार्यकर्ता देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहे।

शिविर में तिलक राज विनायक, रुप सिंह, जयचंद सहारनी, सत्येन्द्र गिरि, मामचंद सैनी, मनी राम बेलरखा, पवन कुमार सैनी, राम रतन एडवोकेट, एम एल सहगल, महेन्द्र सिंह तंवर, रामेश्वर पाल, सतीश रेवाडी, फूल सिंह इन्दौरा, जमशेद राणा, हरदेव सिंह जोश, मनोज पचेरवाल, जगदीश, सतपाल सरोवा सहित सीपीआई के अन्य राज्य स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़्बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

इप्टा अंबिकापुर तथा प्रलेस ने शहीदों को किया याद

अंबिकापुरः 38वें वर्ष लगातार प्रभात फेरी कर 23 मार्च को 'शहीद ए आजम भगत सिंह' को याद किया गया। प्रभात फेरी प्रातः 7 बजे गांधी चौक से महामाया चौक तक संपन्न हुई। जिसमें सैकड़ों की संख्या में नौजवानों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लिए व पर्चे बांटते हुए प्रभात फेरी में इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद और पूंजीवाद मुर्दाबाद के नारों से सड़कें गूंजने लगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं गीत गाकर इप्टा के अध्यक्ष अंजनी पांडे ने शहीदों को याद किया तथा लगातार नारे लगाते हुए प्रभात फेरी महामाया चौक जा पहुंची। स्कूली छात्र छात्राओं में ऊर्जा का संचार होता गया। महामाया चौक पहुंचकर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर त्रिपाठी जी ने कहा–बच्चों को भगत सिंह के विचारों का अध्ययन करना होगा यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि–भगत सिंह ने कहा था– पूंजीवाद अपनी सत्ता के लिए हमेशा धर्म का इस्तेमाल करता है। आज भी वही परिस्थितियां हैं। इसलिए भगत सिंह व अन्य शहीदों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने भगत सिंह के कथन को दोहराते हुए कहा कि–सही आजादी तभी आएगी जब एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण खत्म होगा। अध्यक्ष अंजनी पांडे ने इप्टा की मांग को दोहराते हुए कहा कि कला केंद्र को शहीद पार्क का दर्जा देते हुए वहां पर शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएं। उन्होंने उपस्थित सभी जनों को धन्यवाद देते हुए धरम गुप्ता, माधव राय, संजय शर्मा तथा स्कूलों के प्राचार्य इत्यादि को सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। इस प्रभात फेरी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, पेंशनर यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, सीटू, एटक खासतौर पर ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, उर्सुलाइन, सेंट्रल स्कूल, मणिपुर गर्ल्स स्कूल, विवेकानंद स्कूल के शिक्षकों व प्राचार्य को धन्यवाद दिया। जिनकी प्रेरणा से बालक बालिकाएं प्रभात फेरी में भारी संख्या में उपस्थित थे। उन्होंने गणमान्य नागरिकों को भी धन्यवाद दिया। अंत में पुष्प अर्पण व मौन श्रद्धांजलि के पश्चात प्रभात फेरी संपन्न हुई।

शाकिर अली खान: ...

पेज 5 से जारी...

गालियों–भरा साम्प्रदायिक अभियान चलाया गया।

नवाब के तोड़फोड़वादी षडयंत्रों तथा मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक राजनीति के फलस्वरूप 1939 के अंत में भोपाल प्रजामंडल में फूट पड़ गई। शाकिर अली ने इसकी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया।

आगे चलकर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। इसने स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम अपनाया। इसमें शाकिर अली ने प्रमुख भूमिका अदा की।

गिरफ्तारियां

16 जून 1940 को शाकिर अली समेत कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें जेलों में अत्यंत ही खराब हालत में रखा गया। इसके विरोध में उन्होंने जेल में सत्याग्रह और भूख–हड़ताल आरंभ कर दी। शाकिर अली का वतन करीब 23 पाउंड घट गया।

अपने साथियों के साथ शाकिर अली जुलाई 1942 में रिहा कर दिए गए। उन्होंने प्रजामंडल को पुनर्गठित करके आंदोलन का नया दौर शुरू किया। विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल का नया सिलसिला आरंभ हो गया। शाकिर अली तथा अन्य को पुनः सितम्बर 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया।

1941–46 के दौरान भोपाल प्रजामंडल की कई गतिविधियां आयोजित की गई। 1945 में प्रजामंडल का राज्य सम्मेलन किया गया। कई अखिल भारतीय नेता भोपाल पहुंचे।

प्रजामंडल ने भोपाल कारपोरेशन का चुनाव लड़ा। उसे 15 में से 9 सीटें जीतीं, बावजूद इस बात के कि मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा ने तीव्र साम्प्रदायिक अभियान चलाया।

गंभीर साम्प्रदायिक परिस्थिति और प्रजामंडल की भूमिका

1946–47 में समूचे उत्तर भारत, विशेष कर सीमा प्रदेशों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए। इसका भोपाल के रजवाड़े पर भी प्रभाव पड़ा। मुस्लिम लीग, खाकसार, मुस्लिम नेशनल गार्ड तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों ने दंगे करवाने तथा प्रजामंडल में गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न किया। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने तो अपने घुड़सवार दस्ते मैदान में उतारे जो सैकड़ों की संख्या में थे और जो तलवारें ताने हुए थे।

शाकिर अली खान ने अपने भाषणों में एवं लेखों में मुस्लिम लीग की तीखी आलोचना की। प्रजामंडल ने साम्प्रदायिक दंगे करवाने की कोशिशों का प्रतिरोध किया। शाकिर अली पर शारीरिक हमले भी किए गए लेकिन प्रजामंडल कुल मिलाकर भोपाल को साम्प्रदायिक दंगों से बचा पाने में सफल रहा।

भोपाल में ग्वालियर जैसे पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में शारणार्थी पहुंचने लगे। उनकी सहायता के लिए प्रजामंडल ने बड़े व्यापक पैमाने पर कार्य किया।

शाकिर अली द्वारा तिरंगा फहराया जाना

15 अगस्त 1947 को भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने पर भोपाल रजवाड़े ने इसे मान्यता नहीं दी। शाकिर अली पर वारंट था। फिर भी उन्होंने खंडवा में उस अवसर पर एक आमसभा में भारत का तिरंगा झंडा फहराया। प्रजामंडल ने भोपाल में भारत की आजादी की खुशी में कई आमसभाएं आयोजित कीं और जुलूस निकाले।

भोपाल रजवाड़े ने 1947 में अपनी अलग 'आजादी' की घोषणा की। भोपाल को भारत में 1 जून 1949 को ही मिलाया जा सका। 1948 में राज्य में नवाब के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किए गए जिनमें भारत के साथ विलयन की मांग की गई। इनमें प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। नए भोपाल राज्य को चीफ कमिश्नर के प्रशासन के अंतर्गत 'पार्ट सी' श्रेणी में रखा गया।

इस बीच भोपाल में कई अंतरिम सरकारों का गठन किया गया जिनमें प्रजामंडल की हिस्सेदारी रही। अब प्रजामंडल 'भोपाल कांग्रेस' बन गई। इसके नेतृत्व में भारत के साथ विलयन का आंदोलन तेज हो गया। इस आंदोलन में शाकिर अली खान, बालकृष्ण गुप्त और अन्य की अत्यंत ही सक्रिय भूमिका रही।

इन घटनाओं से पहले प्रजामंडल में आंतरिक मतभेदों के कारण शाकिर अली ने इससे इस्तीफा दे दिया। नवाब ने अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा तथा भोपाल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल किया। शाकिर अली इससे सहमत नहीं थे।

आजादी के बाद 1948 में मध्य भारत क्षेत्र में दो नए राज्यों का गठन हुआः विंध्य प्रदेश और मध्य भारत। उनका निर्माण कई रजवाड़ों के परस्पर विलयन से हुआ। इन दोनों के विलयन से 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ जिसमें भोपाल शामिल हुआ।

कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल

शाकिर अली ने 1952 के आम चुनावों में 'किसान मजदूर मंडल' के उम्मीदवार के रूप में जहांगीराबाद से चुनाव लड़ा। वे दूसरे नम्बर पर आए। उनके खिलाफ भोपाल प्रजामंडल में उनके भूतपूर्व सहयोगी तर्जी मशरीकी खड़े थे।

भोपाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 1952 को एक आमसभा में की गई। इसमें वे लोग शामिल हुए जो प्रजामंडल, कांग्रेस तथा अन्य संगठनों से अलग हुए थे। इनमें शाकिर अली सबसे महत्वपूर्ण थे।

शाकिर अली स्वयं लिखते हैं: ''मेरा झुकाव पहले ही कम्युनिज्म की ओर था। कॉमरेड सज्जाद जहीर, पी.सी. जोशी, डा. अशरफ वगैरह के साथ मेरे जुड़ाव से इसे बल मिला। 1952 में मैं औपचारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया।''

उन्हें 1953 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी एक मजबूत पार्टी बन गई। शाकिर अली 1957 में एच एम एस के उद्धो दास मेहता को हराकर विधानसभा के लिए चुन लिए गए। कांग्रेस और हिन्दू महासभा के उम्मीदवार भी मैदान में थे।

शाकिर अली खान फिर से 1962, 1967 और 1972 में चुन लिए गए। 1959 में भोपाल म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी 30 में से 15 सीटें जीत गई। कांग्रेस को 12 सीटें मिलीं।

बाद में शाकिर अली मध्य प्रदेश पार्टी के राज्य सचिव भी चुने गए। वे राज्य के सबसे ऊंचे और सम्मानित नेता के रूप में उभरे।

शाकिर अली खान की मृत्यु 14 मार्च 1978 को हो गई। पूरा शहर अपने–आप बंद हो गया। हजारों लोगों ने जुलूसों में हिसा लिया। बाद में उनकी याद में स्मारक का निर्माण किया गया।

मुक्ति संघर्ष

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

साप्ताहिक 16 – 22 अप्रैल, 2023

प्रकाशन तिथि: 14.4.2023

दलितों, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के विरोध में जलूस

दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमलों की भर्त्सना के लिए 11 अप्रैल 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वाम दलों, दलित और अल्पसंख्यक संगठनों ने 'चलो विजयवाड़ा' कार्यक्रम को संगठित किया था। यह कार्यक्रम विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली कलाक्षेत्रम से शुरू होना था। पुलिस की प्रदर्शन रोकने की कोशिशों में प्रदर्शन स्थल पर तनाव बना हुआ था। विभिन्न जिलों से बसों और रेल से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे कई लोगों को पुलिस ने बस स्टैन्ड और रेल्वे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया था। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल पर रोकने की कोशिश में शहर में प्रवेश के प्रमुख मार्गों की पुलिस की नाकाबंदी कर रखी थी। कई लोगों को कार्यक्रम वाले दिन की सुबह में ही घर में बंद कर दिया था। पुलिस के दमन के बावजूद लोग तुम्मलपल्ली कलाक्षेत्रम में इकट्ठे हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत में नेताओं ने ज्योतिराव फुले और डा. बी आर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर फूलमालाएं चढ़ाई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर मार्च किया। भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी के साथ तुम्मलपल्ली कलाक्षेत्रम के आस पास पुलिस की तैनाती थी। प्रदर्शन जलूस अभी चला ही था कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ी और उन्हें वहाँ खड़ी पुलिस वैनों में भरने लगी। कुछ नेताओं को पुलिस रोड पर घसीटते हुए ले गई। यहाँ तक कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं छोड़ा।

बाद में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को गवर्नर पेट पुलिस थाने ले जाया गया। आंध्र प्रदेश भाकपा राज्य परिषद के सचिव के रामकृष्ण ने ताड़पल्ली स्थित अपने घर से प्रदर्शन स्थल के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। हालांकि,

राम नरसिम्हा राव

रामकृष्ण चतुराई से जुलूस के शुरुआती बिंदु तक पहुंचने में कामयाब रहे। गिरफ्तार किए गए लोगों में के. रामकृष्ण, पूर्व एमएलसी जल्ली विल्सन, करवदी सुब्बा राव, दलित हक्कुला पोराता समिति (डीएचपी) के राज्य महासचिव बुट्टी रायप्पा, दलित हक्कुला पोराता समिति के संगठन सचिव नाकी लेनिन बाबू, अखिल भारतीय नौजवान सभा राज्य महासचिव, एम रामकृष्ण, आंध्र प्रदेश मिनोरटीस प्रोटेक्सन सोसाइटी के फारूक शुभली, राज्य अध्यक्ष एटक रावुलपल्ली रवींद्रनाथ और अन्य शामिल थे।

भाकपा राज्य सचिव के. रामकृष्ण ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमलों में काफी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के जिले कडप्पा में जिला स्तर के एक अधिकारी डाक्टर अचचन्ना की हत्या कर दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात नहीं की। पुलिस ने अभी तक पंचनामा भी नहीं किया है। हालांकि 24 मार्च को डा. अचचन्ना की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं किया गया था

कोविड–19 महामारी से निपटने में सरकार की अपर्याप्तताओं की आलोचना करने के लिए पिछले साल नरसीपटनम क्षेत्र अस्पताल से निलंबित किए गए डा. के. सुधाकर को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। अंततः डा. सुधाकर ने यातनाओं के कारण दम तोड़ दिया। के. रामकृष्ण ने कहा कि उनके निधन के लिए वाईएसआरसीपी सरकार जिम्मेदार है।

राज्य में वाईएसआरसीपी के नेता हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। वाईएसआरसीपी के एमएलसी अनंत बाबू उनमें से एक हैं जिन्होंने अपने ड्राइवर की हत्या कर शव को टुकड़ों में काट दिया। बाद में शव के टुकड़े ड्राइवर के परिजनों को दिए गए। पुलिस हिरासत से बाहर आने पर एमएलसी को उनके कैडरों ने माला पहनाकर सम्मानित किया। इसी तरह कर्नुल जिले के इरावदा में एक अल्पसंख्यक युवती के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे खुले घूम रहे हैं। अब्दुल सलाम के परिवार के चार सदस्यों की आत्महत्या के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं।

फारूक शुबली ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पिछले चार सालों में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। अमरावती बहुजन जॉइन्ट एक्शन कमेटी के पी बालाकोटैयाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कोई मानव अधिकार नहीं है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.